हिन्दी सान्ध्य दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष : 02 | अंक : 101 | जौनपुर, शनिवार 06 जनवरी 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य : 2 रूपया

नो योर आर्मी फेस्टिवल : सीएम योगी बोले, 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति का प्रतीक है भारतीय सेना

सीएम योगी ने सेना के मध्य कमान (सूर्या कमान) में आयोजित तीन दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का शुभारंभ किया

लखनऊ (एजेन्सी) । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सेना के मध्य कमान (सूर्या कमान) में आयोजित तीन दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने रंगबिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ाकर फेस्टिवल का औपचारिक उद्घाटन किया। इस दौरान सिख रेजिमेंट के जवानों ने साहसिक पंजाबी धुनों पर अपने पारंपरिक शौर्यकला का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें सेना के साजो–सामान के साथ ही अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। सीएम योगी ने सेना के अधिकारियों से विभिन्न हथियारों और सैन्य सामानों के बारे में जानकारी भी ली। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना देश के 140 करोड़ जनता की शक्ति और साहस का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि एक सशक्त सेना ही सुरक्षित और संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकती है। पहली बार देश की राष्ट्रीय राजधानी के बाहर आयोजित हो रहे श्नो योर आर्मीश फेस्टिवल के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि समारोह के लिए लखनऊ स्थित सेंट्रल कमांड को चुना जाना गर्व की बात है। यह प्रदेश के युवाओं को नजदीक से भारतीय सेना को जानने और सेना के शौर्य और पराक्रम को नजदीक से पहचानने का अवसर है। मुख्यमंत्री ने सिख रेजिमेंट के शौर्यकला प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा कि ये भारत की प्राचीन कला है, जिसके जरिए हमारे पारंगत युवा आक्रांताओं को मुंहतोड़ जवाब देते थे। मंख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि प्राचीन युद्धकला को भारतीय सेना ने अपना हिस्सा बनाकर ना सिर्फ इस शौर्यकला को सम्मान दिया है, बल्कि सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को भारत के युवाओं के सामने रखकर सम्मान देने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्नो योर आर्मीश फेस्टिवल के जरिए ना सिर्फ सेना के साजो–सामान और हथियारों की प्रदर्शनी को देखने का अवसर हमें मिल रहा है, बल्कि इसके जरिए सेना की शक्ति, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति की निष्ठा को भी नजदीक से जानने समझने का अवसर मिलेगा। यह सेना के हथियारों, उनकी कार्यशैली, और कार्य कुशलता को भी जानने का अवसर है, जिससे सामान्यतरू जनता अनभिज्ञ रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए लड़ी गई हर लड़ाई में हमारे जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश की सुरक्षा करते हुए हमारे जवानों ने प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। प्रदेश सरकार भी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के हितों के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। सरकार वीरगति प्राप्त करने वाले वीरों के परिजनों को 50 लाख की धनराशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का कार्य करती है। सीएम योगी ने कहा कि देश आज प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। ऐसे में सेना के लिए हथियारों और साजो–सामान के मामले में भी हम तेजी के साथ आत्मनिर्भर हो रहे हैं। उन्होंने यूपी के डिफेंस नोड और 2020 में आयोजित डिफेंस एक्सपो की भी चर्चा की।

श्रीकांत पुजारी को कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली (एजेन्सी)। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किए गए श्रीकांत पुजारी को हुबली की अदालत ने जमानत दे दी। श्रीकांत पुजारी के वकील संजीव बडसाका ने बताया कि हम अदालत के आदेश का स्वागत करते हैं...शर्तें (जमानत की) अभी देखी जानी बाकी हैं, प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं है। कॉपी लेने के बाद हम आवेदन करेंगे। कल शाम तक उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। श्रीकांत पुजारी को मिली जमानत से उनके परिवार में भी खुशी है। श्रीकांत पुजारी के बेटे मंजूनाथ ने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं...धन्यवाद। हालांकि, पूरे मामले को लेकर कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर अशोक ने आरोप लगाया कि हिंदू कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के पीछे का कारण 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्धारित भव्य अभिषेक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के लोगों में डर पैदा करने के लिए एक शकारसेवकश को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि इस महीने राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। बीके हरिप्रसाद पहले ही कर्नाटक में शगोधरा जैसीश घटना की दोबारा एंट्री का बयान दे चुके हैं।

हमले में घायल ईडी सदस्य अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली (एजेन्सी)। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में आज उनके वाहन पर हुए हमले के दौरान घायल हुए ईडी टीम के सदस्यों को कोलकाता के एक स्थानीय अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसको लेकर भाजपा राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर हो गई है। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले पर केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रामाणिक ने कहा कि संदेशखाली में जो हुआ उसकी मैं निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि किसी राज्य में जाकर केंद्रीय एजेंसी पर हमला करने से ज्यादा घृणित कोई मुद्दा नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक केंद्रीय एजेंसी ईडी की टीम पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे संविधान....और देश के संघीय ढांचे पर हमला है। भाजपा नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

इकबाल अंसारी को भी मिला रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता

अयोध्या (एजेन्सी)। अयोध्या भूमि विवाद मामले के पूर्व वादी इकबाल अंसारी को 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के श्प्राणप्रतिष्ठाश समारोह का निमंत्रण मिला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने आज उन्हें निमंत्रण कार्ड सौंपा। इसको लेकर इकबाल अंसारी ने अपनी खुशी भी वयक्त की है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि भगवान राम की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। अयोध्या हिंदू–मुस्लिम–सिख–ईसाई सद्भाव की भूमि है। यह हमेशा बरकरार रहेगा...सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और देशभर के मुसलमानों ने इसका सम्मान किया। इकबाल अंसारी ने कहा कि कहीं कोई विरोध या प्रदर्शन नहीं हुआ...अयोध्या के लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूं। इकबाल अंसारी बाबरी मस्जिद के प्रमुख समर्थक रहे हैं और उन्हें 5 अगस्त, 2020 को आयोजित राम मंदिर के भूमिपूजन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी मिला था। अंसारी उन सैकड़ों लोगों में शामिल थे, जिन्होंने 30 दिसंबर को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कतार में खड़े होकर स्वागत किया था, जब मोदी ने उत्तर प्रदेश में कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अलावा एक पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन और एक नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था।एक वीडियो में इकबाल को प्रधानमंत्री के काफिले पर फूल बरसाते हुए भी देखा जा सकता है। इकबाल के पिता, हाशिम अंसारी, जो भूमि विवाद मामले में सबसे उम्रदराज वादी थे, की 2016 में 95 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, जिसके बाद इकबाल ने अदालत में मामले को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 9 नवंबर, 2019 को, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित स्थल पर एक सरकारी ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया और फैसला सुनाया कि हिंदू पवित्र शहर में एक मस्जिद के लिए वैकल्पिक पांच एकड़ का भूखंड खोजा जाना चाहिए।

राहुल गांधी पर वार करते हुए नड्डा बोले- ये भारत जोड़ नहीं रहे, तोड़ने में लगे हैं

हिमाचल प्रदेश के सोलन में जेपी नड्डा ने भव्य रोड शो किया, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष पर निशाना भी साधा

नई दिल्ली (एजेन्सी)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। सोलन में उन्होंने भव्य रोड शो किया। इसके साथ ही उन्होंने अभिनंदन समारोह को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में नड्डा ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष पर निशाना भी साधा। नड्डा ने कहा कि झूठ बोलकर राजनीति नही चलती है, लोगों को धोखे में रखकर राजनीति नहीं चलती है। लोगों से जुड़ना पड़ता है, उनकी तकदीर बदलनी पड़ती है। और ये काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, इसलिए हमें राजस्थान में जीत मिली, मध्य प्रदेश में जीत मिली और छत्तीसगढ़ में भी जीत मिली। विपक्ष पर वार करते हुए नड्डा ने कहा कि भूपेश बघेल ने गरीबों को दी गई केंद्र सरकार की योजनाओं को लटकाया इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें और उनकी सरकार को लटका दिया। राजस्थान में लोगों को समझ आ गया था कि गहलोत की सरकार महिलाओं पर अत्याचार करने वाली सरकार है, युवाओं के साथ अन्याय करने वाली सरकार है। 19 बार पेपर लीक हुआ, कोई भर्ती नहीं हुई इसलिए प्रदेश की जनता ने उन्हें घर ध्बैठा दिया। उन्होंने कहा कि आज जब देश को बांटने के लिए जाति जाति जाति... चल रही है, तो मोदी जी ने कहा हमारे लिए सिर्फ चार जातियां हैं... महिला, किसान, युवा और गरीब। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ ये अधिक लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है। आयुष्मान योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक लोगों को हर वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो तीन प्रदेशों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान) में जीत हुई है और सभी जगहों पर कमल खिल रहा है... ये मोदी जी के प्रति जनता का अटूट विश्वास और भारत की राजनीति की संस्कृति बदलने के कारण हो रहा है। अपना हमला जारी रखते हुए नड्डा ने कहा कि भारत को तोड़ने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं, अब भारत को जोड़ने की यात्रा पर चले हो। भारत को कमजोर करने वाली धारा 370 को मोदी जी ने हटा दिया, लेकिन कांग्रेस ने धारा 370 हटाने का विरोध किया और अब ये भारत को जोड़ने चले हैं। उन्होंने कहा कि जेएनयू के परिसर में संसद पर हमला करने वाले मास्टरमाइंड के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे कि अफजल हम शार्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और दूसरे दिन राहुल गांधी नारे लगाने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं... आज तक राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी मथुरा की शाही ईदगाह से जुड़ी याचिका

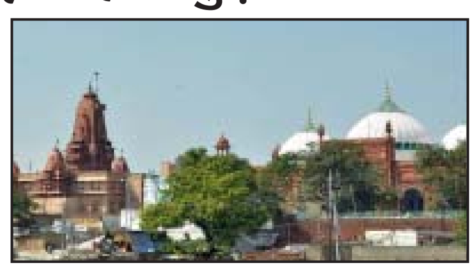

नई दिल्ली (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण और साइट को श्री कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि मुकदमेबाजी की बहुलता उचित नहीं थी जब सिविल सूट का एक बंडल हो। मामले पर फैसला सुनाया जा रहा था। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि आइए मुकदमेबाजी की बहुलता न रखें। आपने इसे जनहित याचिका के रूप में दायर किया, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि जनहित याचिका को पिछले अक्टूबर में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था क्योंकि इस मुद्दे पर कुछ मुकदमे लंबित थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं है। याचिकाकर्ता महेक माहेश्वरी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि जनहित याचिका में 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को भी चुनौती देने की मांग की गई है जो 15 अगस्त, 1947 (राम जन्मभूमि भूमि को छोड़कर) तक मौजूद सभी पूजा स्थलों के चरित्र की रक्षा करता है।

केजरीवाल सरकार की बढ़ेंगी मुसीबतें

नई दिल्ली (एजेन्सी)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में घटिया दवाओं की आपूर्ति की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश दिया है। दिसंबर में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। यह तब हुआ है जब दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने गुरुवार को नकली दवाओं का मामला सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्रालय को भेजा था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पहले जांच एजेंसी को पत्र लिखकर मामले की जांच का अनुरोध किया था। यह कदम सरकारी अस्पतालों में कथित तौर पर नकली दवाओं के पाए जाने पर दिल्ली सतर्कता विभाग की रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है।

कांग्रेस को क्राउड फंडिंग से मिले सिर्फ 11 करोड़, आलाकमान हुआ नाराज

मल्लिकार्जुन खड़गे 18 दिसंबर को औपचारिक रूप से अभियान की शुरूआत की थी उन्होंने खुद 1.38 लाख रुपये का अंशदान दिया

नई दिल्ली (एजेन्सी)। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, कांग्रेस ने पार्टी के लिए संसाधन जुटाने के लिए देशव्यापी क्राउड फंडिंग अभियान, श्डोनेट फॉर देशश की घोषणा की थी। पार्टी की ओर से दावा किया गया था कि यह पहल महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित थी, जिसे सौ साल पहले 1920–21 में लॉन्च किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 दिसंबर को औपचारिक रूप से अभियान की शुरूआत की थी। उन्होंने खुद 1.38 लाख रुपये का अंशदान दिया। इसका बड़ा कारण यह भी था कि कांग्रेस का दान वित्तीय वर्ष 2021–22 में 95.4 करोड़ रुपये से घटकर वित्तीय वर्ष 2022–23 में 79 रुपये करोड़ हो गया है। अब खबर यह है कि कांग्रेस को उम्मीद के अनुरूप दान नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने लोगों से चंदा जुटाने के पार्टी के अभियान की गति पर अप्रसन्नता जतायी और नेताओं से कहा कि वे अपने प्रयासों में तेजी लाएं। सूत्रों के अनसुार पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी वाद्रा सहित शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दो सप्ताह में 11 करोड़ रुपये का चंदा उत्साहजनक नहीं है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन को प्रयासों में तेजी लाने और अभियान को गति प्रदान करने के लिए राज्यों का दौरा करने तथा राज्य इकाइयों के साथ बातचीत करने को कहा गया ताकि पार्टी के लिए अधिक चंदा जुटाया जा सके। सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि पार्टी नेतृत्व ने 14 जनवरी से शुरू हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए अलग से चंदा जुटाने का फैसला किया है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए चंद जुटाने की खातिर दिसंबर में डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया था। खरगे ने नेताओं से कहा कि वे आंतरिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करें, वहीं राहुल गांधी ने उनसे अनावश्यक टिप्पणियां करने से परहेज करने को कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आम जनता से चंदा एकत्र करने के लिए शुरू किए गए पार्टी के 'डोनेट फॉर देश' अभियान के वास्ते चंदा दिया था और कहा कि यह ''सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील'' भारत के लिए उनका योगदान है। गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''मैं आप सभी से दान करने और भारत की आत्मा को बचाने के आंदोलन का हिस्सा बनने का आग्रह करता हूं।'' देश की मुख्य विपक्षी पार्टी 28 दिसंबर को अपने 138वें स्थापना दिवस से पहले इस अभियान के माध्यम से लोगों से 138 रुपये, 1,380 रुपये, 13,800 रुपये या फिर इससे 10 गुना राशि चंदे के रूप में देने की अपील कर रही है।

स्वाति मालीवाल को आप ने दिया इनाम, राज्यसभा भेजने की तैयारी

नई दिल्ली (एजेन्सी)। आम आदमी पार्टी (आप) ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। महिलाओं के अधिकारों की वकालत के लिए जानी जाने वाली स्वाति मालीवाल को नामांकित करने का निर्णय संसदीय मामलों में उनकी शुरुआत होगी।

आप की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) ने संजय सिंह और एनडी गुप्ता को उच्च सदन के सदस्य के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल के लिए मैदान में उतारने का फैसला किया है, क्योंकि उनका वर्तमान कार्यकाल 27 जनवरी, 2024 को समाप्त हो रहा है। सुशील कुमार गुप्ता, जिनका राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल इस महीने समाप्त हो जाएगा, स्वाति मालीवाल के लिए रास्ता बनाएंगे। मामले से परिचित एक व्यक्ति ने बताया कि गुप्ता ने हरियाणा की चुनावी राजनीति में खुद को पूरी तरह से झोंकने की अपनी आकांक्षा व्यक्त की है, जहां आप इस साल के अंत में चुनाव लड़ना चाहती है।

भाजपा विधायक को दो साल की सजा

लखनऊ (एजेन्सी) । उप जिलाधिकारी को धमकाने के मामले में महसी के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को दो वर्ष की सजा हुई है। अदालत ने उन पर 25वव रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाए जाते समय विधायक सुरेश्वर सिंह अदालत में मौजूद नहीं थे। विधायक पर उप जिलाधिकारी कार्यालय में घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने व बाहर निकलने पर धमकी देने का आरोप था। सुरेश्वर सिंह के खिलाफ यह प्रकरण दो सितंबर 2002 को हरदी थाने में दर्ज कराया गया था। अपर सिविल जज प्रवर खंड एवं एसीजेएम एमपी व एमएलए कोर्ट अनुपम दीक्षित ने इस मामले की सुनवाई की। उप जिलाधिकारी के बयान के साथ ही अन्य साक्ष्य का भी परीक्षण कराया।

ईडी की टीम पर हमले को लेकर ममता सरकार पर बरसे अधीर रंजन

पश्चिम बंगाल ईडी की टीम पर हमले को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी सरकार को घेरा, कांग्रेस नेता ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा

नई दिल्ली (एजेन्सी)। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी लगातार तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी के बीच कांग्रेस नेता ममता बनर्जी पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल ईडी की टीम पर हमले को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी सरकार को घेरा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईडी अधिकारियों पर सत्तारूढ़ सरकार के गुंडों के हमले के बाद यह स्पष्ट है कि राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आज वे घायल हुए हैं, कल उनकी हत्या हो सकती है। ऐसी बात मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आपको बता दें कि भीड़ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों के वाहनों को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया, जब वे आज उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर राशन घोटाले के सिलसिले में छापेमारी कर रहे थे। टीएमसी सांसद शांतनु सेन का कहना है कि केंद्रीय बलों से घिरे केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को भड़काया, इसलिए लगातार जवाबी प्रतिक्रियाएं हो रही थीं। वास्तविक तथ्य यह है कि भारत के लोग इस गहरी साजिश को रोजाना दिल्ली से तैयार और निगरानी करते हुए देखकर निराश हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले पर केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रामाणिक ने कहा कि संदेशखाली में जो हुआ उसकी मैं निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि किसी राज्य में जाकर केंद्रीय एजेंसी पर हमला करने से ज्यादा घृणित कोई मुद्दा नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक केंद्रीय एजेंसी ईडी की टीम पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे संविधान....और देश के संघीय ढांचे पर हमला है। भाजपा नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हम जांच करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब किसी राज्य में बार–बार ऐसी घटनाएं होती हैं तो इससे पता चलता है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो रही है और कानून व्यवस्था बाधित है। पलटवार में तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने कहा कि संदेशखाली में जो हुआ वह उकसावे का असर था। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय एजेंसियां ध्और बल भाजपा के निर्देश पर किसी न किसी टीएमसी नेता या कार्यकर्ताओं को परेशान करने, नकारात्मक बयान फैलाने और लोगों को भड़काने के लिए उनके आवास पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे आरोप मिल रहे हैं और कल संदेशखाली में यही हुआ।

हिटलर की तरह काम कर रही बीजेपी, शरद पवार बोले- गोमूत्र और झूठे प्रोपेगेंडा पर ही फोकस

नई दिल्ली (एजेन्सी)। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने भाजपा पर कटाक्ष किया और कहा कि पार्टी हिटलर के प्रचार तंत्र की तरह काम कर रही है। पवार ने यह भी कहा कि जिनके पास सत्ता है उन्हें सिर्फ गोमूत्र दिखता है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए और भाजपा का जिक्र करते हुए, पवार ने कहा कि केवल आरएसएस के कार्यक्रम ही उन्हें दिखाई देते हैं। राकांपा प्रमुख ने कहा कि निजीकरण, गलत प्रचार फैलाना, मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरत और आक्रामक राष्ट्रवाद ये भाजपा के एजेंडे के मूल में मुद्दे हैं। पवार ने कहा कि भाजपा सत्ता में है, उन्होंने आक्रामक प्रचार प्रणाली स्थापित की है। यह जर्मनी में हिटलर के प्रचार तंत्र की तरह काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में सत्ता से बाहर है। देश में भाजपा के लिए माहौल अनुकूल नहीं है। प्रधानमंत्री केवल गारंटी देते हैं, जो हैं कभी पूरा नहीं हुआ। इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने पवार की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा, देश विज्ञान के साथ आगे बढ़ेगा। पत्रकारों से बात करते हुए, राउत ने कहा, शरद पवार ने जो कहा, उसमें कुछ भी गलत नहीं है।

सम्पादकीय

उम्मीदवारों की ऐसी फौज उतारेगी भाजपा जिसके आगे विपक्ष को पहले दिन से हार का भय सतायेगा

केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के मिशन को कामयाब करने के लिए भाजपा जीतोड़ प्रयास कर रही है। चुनाव प्रचार अभियान को अंतिम रूप देने के अलावा पार्टी के तमाम नेताओं की भूमिका भी तय की जा चुकी है। जहां तक लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के चयन की बात है तो यह काम भाजपा बहुत पहले ही शुरू कर चुकी थी और अब यह कार्य अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है। पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द जारी होने की अटकलों के बीच चर्चाएं यह भी हैं कि इस बार भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हम आपको याद दिला दें कि अमित शाह ने भी 2019 में भाजपा अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपना पहला लोकसभा चुनाव गुजरात के गांधीनगर से लड़ा था। भाजपा ने लोकसभा चुनावों में प्रत्येक सीट पर 50 प्रतिशत से ज्यादा मत हासिल करने के लिए अपने संगठन के तंत्र को दुरुस्त करने के बाद उम्मीदवारों के तौर पर ऐसी फौज उतारने का निर्णय लिया है जिसके आगे नामांकन भरते हुए विपक्ष के नेताओं को हार का भय पहले दिन से सताने लगे। इसके लिए भाजपा उम्मीदवारों के चयन के लिए कड़े और बड़े पैमाने तय करके आगे बढ़ रही है। हाल ही में भाजपा की ओर से अपने सांसदों के बारे में जनता की राय जानने के लिए नमो एप पर एक सर्वे भी शुरू किया गया था जिस पर लोगों ने जो फीडबैक दिया उसको पार्टी ने काफी गंभीरता के साथ लिया है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि हाल में संपन्न पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान देखने को मिला था कि पार्टी ने कई सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ाया और यह फॉर्मूला काफी सफल साबित हुआ था। यही नहीं, भाजपा हाल में कई चुनावों में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को बदल कर नये चेहरों को मौका देने का सफल प्रयोग भी कर चुकी है इसीलिए माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन में भी भाजपा हाल के अनुभवों को देखते हुए निर्णय लेगी। उल्लेखनीय है कि भाजपा आलाकमान ने साल 2023 के अंत में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में अपने चुनावी अभियान को अंतिम रूप दे दिया था और अब नये साल पर पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक में उम्मीदवार चयन से जुड़े मुद्दों पर गौर किया गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में एक कमेटी का भी गठन किया गया जोकि असंतुष्ट नेताओं से संपर्क कर उन्हें मनाने का काम करेगी साथ ही कमेटी यह भी देखेगी कि चुनावों के दौरान दूसरे दलों से आने वाले किन लोगों को भाजपा में शामिल कराना है और किन्हें नहीं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य दलों के कई कद्दावर नेता और समाज के विभिन्न क्षेत्रों की मशहूर हस्तियां भाजपा में शामिल होने वाली हैं। जहां तक लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की बात है तो बताया जा रहा है कि पहली सूची जल्द ही जारी हो सकती है। पहले माना जा रहा था कि यह सूची मकर संक्रांति के बाद आयेगी क्योंकि अभी खरवास चल रहा है जिसमें शुभ काम नहीं किये जाते लेकिन अब माना जा रहा है कि यह सूची पहले भी आ सकती है। दरअसल भाजपा ने पिछले साल पहली बार पितृपक्ष के दौरान ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी थी जिसको लेकर सवाल उठे थे कि शुभ मुहूर्त और शुभ–अशुभ का खास ध्यान रखने वाली भाजपा ने आखिर पितृपक्ष में कैसे अपनी सूची जारी कर दी? लेकिन समय से पहले उम्मीदवारों की घोषणा करना पार्टी के पक्ष में गया इसीलिए माना जा रहा है कि जिन सीटों पर भाजपा को पिछले चुनावों में जीत नहीं मिली थी या जहां भाजपा का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था वहां के उम्मीदवारों की सूची शीघ्र ही सामने आ सकती है ताकि उम्मीदवारों को प्रचार के लिए अच्छा खासा समय मिल सके। साथ ही एक ओर जहां अन्य दल अभी सीटों के बंटवारे पर चर्चा ही नहीं शुरू कर पाये हैं वहीं भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करके विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर लेना चाहती है। बताया जा रहा है कि भाजपा ने इस बार बड़ी संख्या में अपने राज्यसभा सांसदों को भी लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है ताकि संसद के ऊपरी सदन में लंबे समय से जमे चेहरों की जगह नये चेहरों को मौका दिया जा सके। इसके लिए तय किया गया है कि भाजपा शासित राज्यों के चुनिंदा राज्यसभा सांसदों को लोकसभा चुनाव लड़ाया जायेगा। भाजपा शासित राज्यों का चयन इसलिए किया गया है ताकि सीट छोड़ने वाले व्यक्ति की जगह आसानी से पार्टी का दूसरा उम्मीदवार राज्यसभा पहुँच सके। इसके अलावा उन राज्यसभा सांसदों को भी चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है जिनका कार्यकाल हाल ही में खत्म हुआ या जल्द ही खत्म होने वाला है।

पहले पिछली गलतियों के लिए माफी मांगे, फिर न्याय यात्रा निकाले कांग्रेस

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 14 जनवरी को मणिपुर से भारत न्याय यात्रा करने का ऐलान किया है। पार्टी के अनुसार, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एकता, प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाने के बाद गांधी देश के लोगों के लिए न्याय मांगेंगे। राहुल गांधी 6200 किलोमीटर की यात्रा के दौरान 14 राज्यों को कवर करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के बंटवारे के फैसले से लेकर लंबे कालखंड तक तमाम अवसरों पर अन्याय किया है, वो आखिरकार किस मुंह से न्याय यात्रा निकालेगी? 1947 में देश के बंटवारे को लेकर कितने किस्से हम और आप ने सुन रखे हैं, लेकिन जिन्होंने बंटवारे में अपना घर–बाहर और अपने को खोया है, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि नेहरू की प्रधानमंत्री बनने की जिद ने बंटवारा करवाया। मेरे पूर्वजों ने भी बंटवारे का दंश सहा है। हिन्दुस्तान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बंटवारे की पीड़ितों के साथ हर कदम पर अन्याय किया। रिफ्यूजी कैंपों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं थी। बंटवारे के बाद कई महीनों और वर्षों तक शरणार्थियों के निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं बने थे। शरणार्थियों को कोई विशेष दर्जा, आरक्षण या छूट सरकार ने नहीं दी। नतीजतन, शरणार्थियों की पूरी एक पीढ़ी शिक्षा, नौकरी और तमाम अन्य क्षेत्रों में पिछड़ गई। शरणार्थियों को बंटवारे से ज्यादा दर्द और तकलीफ नेहरू सरकार की बेरूखी, बेइंसाफी और बदइंतजामी ने दिया। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके दो सिख अंगरक्षकों ने की। इसके अगले दिन से ही दिल्ली और देश के दूसरे कुछ हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों में सिखों के घरों, दुकानों को जलाया और लूटा गया और उनको मौत के घाट उतारा गया। दिल्ली और अन्य स्थानों पर हत्यारों और लुटेरों की भीड़ का नेतृत्व ज्यादातर कांग्रेस के नेता कर रहे थे। प्रेस एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इन दंगों में दिल्ली में ही लगभग 2700 लोग मारे गए थे और देशभर में मरने वालों का संख्या 3,500 के करीब थी। 19 नवंबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी व उनके पुत्र राजीव गांधी ने दिल्ली बोट क्लब में इकट्ठा हुए लोगों के हुजूम के सामने कहा कि, 'जब इंदिरा जी की हत्या हुई थीघ्, तो हमारे देश में कुछ दंगे–फसाद हुए थे। हमें मालूम है कि भारत की जनता को कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है।' प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शब्दों में कोई जिक्र नहीं था उन हजारों सिखों का जो अनाथ और बेघर हो गए थे बल्कि ये वक्तव्य उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। दंगों के 21 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में इसके लिए माफी मांगी और कहा कि जो कुछ भी हुआ, उससे उनका सिर शर्म से झुक जाता है। लेकिन क्या इतना कहने भर से ही सरकार का फर्ज पूरा हो गया? क्या इससे आजाद भारत के सबसे सबसे बुरे हत्याकांड की यादें मिट गईं? सिख दंगों के दोषी कांग्रेसी नेता गांधी परिवार के खास हैं। गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने आज तक हजारों निर्दोष सिखों के कत्लेआम के लिए माफी नहीं मांगी है। साल 1984 में दो दिसंबर की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस के रिसाव के असर से सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 15 हजार लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी देश के पीएम थे। हादसे के वक्त यूनियन कार्बाइड कंपनी का सीईओ अमेरिकी कारोबारी वारेन एंडरसन था।

उल्फा-सरकार शांति समझौता: असम में फिर नई उम्मीद

चंदन कुमार शर्मा

विगत 29 दिसंबर को केंद्र, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (उल्फा) के वार्ता समर्थक गुट के बीच एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्व शर्मा ने समझौते को श्ऐतिहासिकश बताया और कहा कि यह राज्य में दशकों से चल रही हिंसा खत्म करेगा और विकास एवं समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत होगी। एक संप्रभु असम की मांग के साथ भारत राष्ट्र के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की घोषणा करते हुए 1979 में उल्फा का गठन किया गया था। तब से, इस सशस्त्र संघर्ष में दस हजार से अधिक लोगों की जान गई है, अनेक लोग जीवन भर के लिए अपंग हो गए और कई लोगों को अन्य प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। इसलिए असम की जनता लंबे समय से समस्या का राजनीतिक समाधान चाहती रही है। ऐसी ही एक पहल 2005 में हुई थी, जब उल्फा नेतृत्व द्वारा पीपुल्स कंसल्टेटिव ग्रुप (पीसीजी) नामक एक समूह का गठन किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार के साथ परामर्श करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता डॉ. इंदिरा गोस्वामी के नेतृत्व में असमिया नागरिक समाज के सदस्य शामिल थे। समूह ने केंद्र सरकार के साथ कई दौर की चर्चा की। लेकिन 2009 में उल्फा प्रमुख अरबिंद राजखोवा सहित संगठन के शीर्ष नेताओं को बांग्लादेश में गिरफ्तार कर असम लाए जाने के बाद घटनाओं ने अलग मोड़ ले लिया। संगठन के कई महत्वपूर्ण नेता या तो सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तार नेतृत्व ने 2011 में पीसीजी को मध्यस्थ न रखने और केंद्र सरकार के साथ सीधे वार्ता करने का फैसला किया। जबकि म्यांमार स्थित उल्फा के कमांडर इन चीफ और कट्टरवादी परेश बरुआ ने इसे श्असांविधानिकश करार दिया। हालांकि इस बीच उल्फा नेतृत्व ने, जिसे वार्ता समर्थक समूह कहा जाता है, असम के नागरिक समाज से कहा कि वे समस्या के समाधान के लिए उनका मार्गदर्शन करें। उसके बाद मई, 2011 में प्रमुख बुद्धिजीवी हिरेन गोहेन के नेतृत्व में गुवाहाटी में नागरिक समाज ने सम्मेलन कर उल्फा नेतृत्व को केंद्र सरकार के समक्ष उठाई जाने वाली मांगों का एक चार्टर सौंपा। मांगों के चार्टर में राज्य में उत्पन्न राजस्व, प्राकृतिक संसाधनों, योजना प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए राज्य की शक्ति मजबूत करने और एक सुरक्षित जनसांख्यिकीय स्थिति के साथ–साथ त्वरित और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के माध्यम से असम (इसके लोगों) को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण देने के लिए सांविधानिक संशोधन का प्रावधान शामिल था। हालांकि, परेश बरुआ ने केंद्र सरकार के साथ चर्चा के महत्व को खारिज नहीं किया, लेकिन वह इस बात पर अड़े रहे कि चर्चा संगठन की मूल मांग–राजनीतिक संप्रभुता और आर्थिक स्वायत्तता–पर होनी चाहिए। कई दौर की चर्चा के बाद हालिया संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

गिरफ्तार नेतृत्व ने 2011 में पीसीजी को मध्यस्थ न रखने और केंद्र सरकार के साथ सीधे वार्ता करने का फैसला किया। जबकि म्यांमार स्थित उल्फा के कमांडर इन चीफ और कट्टरवादी परेश बरुआ ने इसे श्असांविधानिकश करार दिया। हालांकि इस बीच उल्फा नेतृत्व ने, जिसे वार्ता समर्थक समूह कहा जाता है, असम के नागरिक समाज से कहा कि वे समस्या के समाधान के लिए उनका मार्गदर्शन करें। उसके बाद मई, 2011 में प्रमुख बुद्धिजीवी हिरेन गोहेन के नेतृत्व में गुवाहाटी में नागरिक समाज ने सम्मेलन कर उल्फा नेतृत्व को केंद्र सरकार के समक्ष उठाई जाने वाली मांगों का एक चार्टर सौंपा। मांगों के चार्टर में राज्य में उत्पन्न राजस्व, प्राकृतिक संसाधनों, योजना प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए राज्य की शक्ति मजबूत करने और एक सुरक्षित जनसांख्यिकीय स्थिति के साथ–साथ त्वरित और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के माध्यम से असम (इसके लोगों) को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण देने के लिए सांविधानिक संशोधन का प्रावधान शामिल था।

बेशक यह समझौता स्वदेशी समुदायों के हितों की रक्षा कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का वादा करता है, लेकिन यह कैसे किया जाएगा, यह बहुत स्पष्ट नहीं है। लगता है कि बाकी के अधिकांश प्रावधान, जैसे–मतदाता सूची से अवैध विदेशियों के नाम हटाने के लिए मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया की पुनरू जांच, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की पुनरू जांच (जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है), भूमि संबंधी आंकड़ों का डिजिटलीकरण, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मजबूत निगरानी, भूमिहीन स्वदेशी लोगों को जमीन देना आदि कोई नई बात नहीं है। इनमें से कुछ और राज्य में नई रेलवे लाइनों और राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना का जिक्र समझौते में किया गया है, जो सरकार के पहले से किए जा रहे कार्यों का ही विस्तार है। परेश बरुआ ने इस त्रिपक्षीय समझौते को श्शर्मनाकश और राज्य के लोगों के साथ धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि वह चर्चा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन तब तक वार्ता की मेज पर नहीं बैठ सकते, जब तक असम की स्वायत्तता को मुद्दे पर चर्चा न हो। राज्य की जनता की प्रतिक्रिया भी बहुत ठंडी है। मीडिया और विपक्षी पार्टियां भी इसकी आलोचना कर रही है। उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के कुछ लोगों ने कहा कि वे समझौते की शर्तों से अनभिज्ञ थे और खुश नहीं हैं। वास्तव में समझौते की आलोचना इसलिए हो रही है, क्योंकि यह उल्फा के राजनीतिक मुद्दों को कमजोर करने वाले कुछ आर्थिक पैकेज तक ही सीमित है। वार्ता समर्थक गुट ने भी स्वीकार किया है कि वे अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद समझौते से अधिक कुछ हासिल नहीं कर सके। मौजूदा परिस्थितियों में वे अधिक सौदेबाजी करने की स्थिति में भी नहीं थे। इसलिए समझौते की सीमित सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसके मौजूदा प्रावधानों को कैसे लागू किया जाता है।

सभी जानते हैं कि परेश बरुआ उल्फा की मुख्य ताकत बने हुए हैं। वह म्यांमार से ऑपरेशन चलाते हैं और हाल ही मीडिया में खबर आई कि असम के युवाओं में उनका साथ देने के लिए म्यांमार जाने का नया चलन शुरू हुआ है। वार्ता समर्थक गुट समेत सभी जानते हैं कि उल्फा समस्या का समाधान तभी होगा, जब परेश बरुआ चर्चा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हिमंत विस्व शर्मा भी कई बार इसका संकेत दे चुके हैं। ताजा समझौते के पीछे मुख्यमंत्री की भूमिका स्पष्ट नजर आ रही है। इस समझौते ने परेश बरुआ की प्रासंगिकता को खत्म करने का अवसर दिया था। ऐसा क्यों नहीं किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए आलोचकों ने इस समझौते को लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया समझौता बताया है। लेकिन जनता की प्रतिक्रिया देखते हुए लगता नहीं है कि इससे सत्तारूढ़ दल को कोई लाभ होगा। समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले ऊपरी असम में सुरक्षा बलों पर उल्फा के नए हमले हुए। कुछ उल्फा कैडर मारे गए और कुछ गिरफ्तार हुए। यह उल्फा (स्वतंत्र) के नाम वाले परेश बरुआ के विद्रोही गुट की ताकत का प्रदर्शन है या यह नियंत्रण में रखने के लिए सरकार की सक्रिय भूमिका का नतीजा है–यह कहना कठिन है। मौजूदा समझौते की प्रकृति और समझौते के बाद हस्ताक्षर करने वाले उल्फा नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री के बयानों से लगता है कि अभी भविष्य के गर्भ में बहुत कुछ है। गिरफ्तार नेतृत्व ने 2011 में पीसीजी को मध्यस्थ न रखने और केंद्र सरकार के साथ सीधे वार्ता करने का फैसला किया। जबकि म्यांमार स्थित उल्फा के कमांडर इन चीफ और कट्टरवादी परेश बरुआ ने इसे श्असांविधानिकश करार दिया। हालांकि इस बीच उल्फा नेतृत्व ने, जिसे वार्ता समर्थक समूह कहा जाता है, असम के नागरिक समाज से कहा कि वे समस्या के समाधान के लिए उनका मार्गदर्शन करें। उसके बाद मई, 2011 में प्रमुख बुद्धिजीवी हिरेन गोहेन के नेतृत्व में गुवाहाटी में नागरिक समाज ने सम्मेलन कर उल्फा नेतृत्व को केंद्र सरकार के समक्ष उठाई जाने वाली मांगों का एक चार्टर सौंपा। मांगों के चार्टर में राज्य में उत्पन्न राजस्व, प्राकृतिक संसाधनों, योजना प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए राज्य की शक्ति मजबूत करने और एक सुरक्षित जनसांख्यिकीय स्थिति के साथ–साथ त्वरित और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के माध्यम से असम (इसके लोगों) को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण देने के लिए सांविधानिक संशोधन का प्रावधान शामिल था। हालांकि, परेश बरुआ ने केंद्र सरकार के साथ चर्चा के महत्व को खारिज नहीं किया, लेकिन वह इस बात पर अड़े रहे कि चर्चा संगठन की मूल मांग–राजनीतिक संप्रभुता और आर्थिक स्वायत्तता–पर होनी चाहिए।

कई दौर की चर्चा के बाद हालिया संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बेशक यह समझौता स्वदेशी समुदायों के हितों की रक्षा कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का वादा करता है, लेकिन यह कैसे किया जाएगा, यह बहुत स्पष्ट नहीं है। लगता है कि बाकी के अधिकांश प्रावधान, जैसे–मतदाता सूची से अवैध विदेशियों के नाम हटाने के लिए मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया की पुनरू जांच, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की पुनरू जांच (जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है), भूमि संबंधी आंकड़ों का डिजिटलीकरण, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मजबूत निगरानी, भूमिहीन स्वदेशी लोगों को जमीन देना आदि कोई नई बात नहीं है। इनमें से कुछ और राज्य में नई रेलवे लाइनों और राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना का जिक्र समझौते में किया गया है, जो सरकार के पहले से किए जा रहे कार्यों का ही विस्तार है।

हर महीने एक अच्छी आदत आपको सालभर ऊर्जावान रखेगी

नया साल, वही हाल। कुछ सोचा था कि ये बदलेंगे, वो बदलेंगे। दो दिन किया, फिर हिम्मत टूट गई। खुन्नस में आकर बोला, छोड़ो। जो होना है वो होने दो। आपकी व्यथा समझती हूं। पर निराश ना हों। आपने जो भी न्यू ईयर रिजॉल्यूशनलि या, उसे रखने का एक सरल उपाय है। जानने के लिए पढ़ते जाइए। पहली बात। आपने निश्चय किया कि मैं इस साल 10 किलो वजन घटाऊंगी। तो दो दिन दिल कड़ा कर सूप, सलाद, फल का सेवन किया। तीसरे दिन जब दाल–रोटी देखी तो रहा ना गया, उस पर टूट पड़ीं। भाई माउंट एवरेस्ट पर आपको चढ़ना है तो उसके लिए तैयारी जमीन पर शुरू करनी होगी। आप बस इतना सोच लो कि हर महीने मुझे एक अच्छी आदत अपनानी है। पहली आदतरू हरी सब्जी का सेवन अधिक करना है। हमारी ज्यादातर महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी है। हरी सब्जी खाते हैं पर रो–धोकर। रोज पालक–पुदीना–तुलसी के सेवन का सरल उपाय– बनाइए ग्रीन स्मूदी। रेसिपी आपको गूगल पर मिल जाएगी। सुबह चाय पीने के पहले पीजिए। कुछ ही दिन में आपको चस्का लग जाएगा। दूसरी आदतरू चाय में शकर डालना बंद कीजिए। अगर आप दिन में तीन कप चाय पीती हैं– एक चम्मच शकर के साथ– तो महीने में औसत 350 ग्राम आपके पेट में गए। सालभर का हिसाब करें तो 4 किलो शकर आपने सिर्फ चाय में ले ली! तो फिर चीनी–मुक्त चाय से फायदा तो होना ही होना है। तीसरी आदत सात्विक स्टाइल से भोजन कीजिए। यानी कि वही दाल–सब्जी–रोटी मगर तीनों की मात्रा प्लेट में एक तिहाई होनी चाहिए। दाल और सब्जी बड़े कटोरे में परोसिए, रोटी की क्वांटिटी कम करें। गेहूं के अलावा नचनी, ज्वार या बाजरे की रोटी भी खाइए। सात्विक भोजन से पेट एकदम हल्का महसूस होगा। तो ये भी जरूर ट्राय कीजिए। अब तन से हम चलते हैं मन की ओर। चौथी आदत फोन पर फालतू बातें करना बंद कीजिए। कोई आपको अपनी सास की बातें सुना रही है। कोई अपने बॉस का गाना गा रहा है। आप शिकायतों के चक्रव्यूह में ना फंसिए। कुछ और टॉपिक शुरू कीजिए और अगर अगला ना माने तो कोई बहाना बनाकर फोन रख दीजिए। अपना 'पीस ऑफ माइंड' सर आंखों पर। पांचवीं आदत अपने अंदर गुस्सा हो तो नोटबुक उठाइए और उसमें अपने इमोशंस की उल्टी कर दीजिए। अगर डर है कि कोई पढ़ लेगा तो लिखे हुए पन्ने फाड़कर जला डालिए। फिर भी कुछ बचा–खुचा हो तो तेज वॉल्यूम पर पंजाबी गाने चलाकर 'गुस्सा डांस' कीजिए। ये क्या होता है– जो करेगा खुद जान जाएगा, सुकून जरूर मिलेगा। छठवीं आदत फोन व्रत। इसका मतलब ये कि दिन में चार घंटे ऐसे हों जिसमें आप अपने फोन की तरफ बिल्कुल ना देखें। सबको इन्फॉर्म कर दो कि 12 से 4 के बीच मैं अवेलेबल नहीं हूं। दो–चार दिन मन मचलेगा, फिर आप सेटल हो जाएंगी। शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, चिड़ियों की आवाज और बच्चों की किलकिलाहट सुनाई देगी। बताइए एक महीने में एक आदत जोड़ना कोई मुश्किल काम है क्या? आप कर सकती हैं। जब एक आदत पक्की हो जाए, उस पर एक और बैठाएं। इसे कहते हैं 'हैबिट स्टैकिंग'। ऊंची बिल्डिंग बनती है ईंट के ऊपर ईंट रखकर। छह महीने बाद आप पाएंगी कि मैं पहली मंजिल पर पहुंच गई। फिर दूसरी। फिर तीसरी। और यहां से दुनिया कुछ अलग दिख रही है। मेहनत जो की है, रंग ला रही है। रग–रग में ऊर्जा आ रही है। क्योंकि अब वश में हैं तन और मन। हर दम नहीं मांगता ईजी फन। अपने आप से संघर्ष जो किया, उस इंवेस्टमेंट ने बढ़िया रिटर्न दिया। एक दिन आप पहुंचेंगी अपने गोल पर। कोई पूछे तो बताना दिल खोलकर। जो मैंने किया आप कर सकती हैं। क्योंकि अंदर अपार शक्ति है। तो ये आदत पर आदत वाला नुस्खा जरूर अपनाइए। कौन–सी आदत चुनी, मुझे ईमेल पर बताइए। महीने के अंत में प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिएगा। खुद के साथ चीटिंग ना कीजिएगा। एक अपनी कोई सहेली या साथी चुन लीजिए। थोड़ा एक–दूसरे को मोरल सपोर्ट कीजिए। जब तक 2025 आएगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को देखकर ख्याल आएगा। अरे मुश्किल नहीं, हो जाएगा। सबको स्वास्थ्य और शांति, जब हो आदतों की क्रांति। बताइए एक महीने में एक आदत जोड़ना कोई मुश्किल काम है क्या? आप कर सकती हैं। जब एक आदत पक्की हो जाए, उस पर एक और बैठाएं। इसे कहते हैं 'हैबिट स्टैकिंग'। ऊंची बिल्डिंग बनती है ईंट के ऊपर ईंट रखकर। छह महीने बाद आप पाएंगी कि मैं पहली मंजिल पर पहुंच गई।

नये साल से उम्मीदें तो बहुत हैं मगर कई चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं

यह समझ देखी गयी है कि नयेपन के जादुई आकर्षण के जागते ही हम पुरानेपन को उतार फेंकना चाहते हैं। हमने बीते वर्ष में श्रेष्ठताओं की उपलब्धि पर सात्विक गर्व करने की अनेक स्थितियों को रचा है लेकिन हम सबके लिए और देश के लिए भी आने वाले वर्ष कुछ महत्वपूर्ण करणीय कार्य है। निश्चित ही नया साल हमेशा की तरह कुछ सवाल भी लेकर आया है। ऐसे सवाल जिनका हल निकाले बिना शायद हम संतुष्ट न हो पाएं और नये भारत–सशक्त भारत का सपना आधा–अधूरा ही कहा जायेगा। ऐसे नए–पुराने सवाल हर नए साल में सामने आते रहे हैं। कुछ सवालों को हल करने में हम सफल रहे, लेकिन कुछ सवाल हमेशा की तरह अनुत्तरित ही रह गए। सच तो यह है कि नई जिन्दगी की शुरुआत ही नया वर्ष है।

ललित गर्ग

नया साल प्रारंभ हो गया है तो हर बार की तरह इस बार भी नई उम्मीदें, नया विश्वास एवं नया धरातल लाया है। बीत गया एक और साल। नये की स्वीकृति के साथ पुराने को अलविदा कह देने की सामान्य सोच रही है। यह समझ देखी गयी है कि नयेपन के जादुई आकर्षण के जागते ही हम पुरानेपन को उतार फेंकना चाहते हैं। हमने बीते वर्ष में श्रेष्ठताओं की उपलब्धि पर सात्विक गर्व करने की अनेक स्थितियों को रचा है लेकिन हम सबके लिए और देश के लिए भी आने वाले वर्ष कुछ महत्वपूर्ण करणीय कार्य है। निश्चित ही नया साल हमेशा की तरह कुछ सवाल भी लेकर आया है। ऐसे सवाल जिनका हल निकाले बिना शायद हम संतुष्ट न हो पाएं और नये भारत–सशक्त भारत का सपना आधा–अधूरा ही कहा जायेगा। ऐसे नए–पुराने सवाल हर नए साल में सामने आते रहे हैं। कुछ सवालों को हल करने में हम सफल रहे, लेकिन कुछ सवाल हमेशा की तरह अनुत्तरित ही रह गए। सच तो यह है कि नई जिन्दगी की शुरुआत ही नया वर्ष है। यह पुरुषार्थ का सन्देश है, अधूरे रहे कामों एवं संकल्पों को पूरा करने का। इन क्षण जड़ताओं को तोड़कर मुक्त होती है हमारे विकास की उजली संभावनाएं। यह अच्छाइयों एवं अधूरे रहे कार्यों को पूरा करने की ओर मुड़ने की प्रेरणा है। अर्धशून्य ढर्रे की जीवनशैली एवं विकास योजनाओं को बदलने का बुजुर्गी सुझाव है। समस्या जब बहुत चिन्तनीय बन जाती है तो उसे बड़ी गंभीरता से नया मोड़ एवं रफ्तार देने की जरूरत है। शिक्षा, चिकित्सा एवं पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं से जुड़े ऐसे ही अफसोस के अहसास हमारे लिये गंभीर होने चाहिए। आजादी के अमृत काल में भी शिक्षा, चिकित्सा एवं पर्यावरण से जुड़ी चिन्ताओं का गहन बना रहना हमारी विकास यात्रा पर एक सवालिया निशान है। शिक्षा जगत से जुड़ी एक खबर सामने आई है, वह यह कि बढ़ती महंगाई और बदलते नियमों से विदेशों में पढ़ाई मुश्किल हुई है। सब जानते हैं कि शिक्षा हर परिवार के लिए एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। हर मां–बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं। कई बार अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों को विदेश भी भेजना पड़ता है। सवाल यह है कि आबादी के हिसाब से दुनिया का पहले नंबर वाला देश क्या अपने यहां ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं करा सकता? यह सवाल करोड़ों बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सरकार के अनूठे एवं व्यापक प्रयत्नों के बावजूद शिक्षा और चिकित्सा के लगातार महंगे होने की चिन्ता से हर कोई परेशान है। शिक्षा और चिकित्सा को व्यवसाय बना देने एवं निजी हाथों में सौंप देने से ही दोनों महंगी हुई है, आम आदमी तक उसकी पहुंच जटिल होती गयी है। इस बात पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने चिन्ता जताते हुए कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही हर व्यक्ति की मूलभूत जरूरत है पर दोनों ही महंगी और दुर्लभ हो रही हैं। इसकी वजह जनसंख्या के मुताबिक उपलब्धता की कमी और व्यावसायिकता है।' नये भारत के निर्माण के साथ समय की इस दस्तक को सुनें। निश्चित ही यह भारत की समृद्धि एवं विश्व प्रतिष्ठा की दृष्टि से एक अनूठा उपक्रम हो सकता हैं, लेकिन प्रश्न भारतीय छात्रों का है, उनकी शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का है। महंगी होती शिक्षा आम जनजीवन से दूर होती जा रही है, ऐसे में भारतीय छात्रों की सूध कौन लेगा? शिक्षा पर लंबे–लंबे भाषण देने वाले राजनेता, शिक्षाविद, अधिकारी और मंत्री भी देश की इन स्थितियों से परिचित हैं। बसों में मूंगफली बेचते हुए, स्टेशनों पर भीख मांगते हुए, चौराहों पर भुट्टा भूजते हुए, फैक्ट्रियों में बिसलरी की बोतलों में पानी भरते हुए, सड़क के किनारे टाट पर सब्जी बेचते या चाट का ढेला लगाते हुए इन बच्चों को कौन नहीं देखता है। ऐसा इन्हें क्यों करना पड़ता है? यह जानने की कोशिश कितने लोग करते हैं? रिक्शा, ऑटोरिक्शा, बस चलाने वाले ड्राइवरों के पीछे की भी कहानी ऐसी ही होती है। नीति–नियंता लोग अपने निजी ड्राइवर, नौकर या कामवाली बाई की पारिवारिक स्थिति के बारे भी विचार कर लेते तो भी इस तरह की स्थितियों के बारे में बहुत कुछ आसानी से समझ लेते। कहीं–कहीं ये भी देखने को मिलता है कि जिन बच्चों की खिलौनों से खेलने की उम्र होती है वही बच्चे मेला, हाट–बाजार में खिलौना बेचते हुए मिलते हैं। किताबों से तो उनका दूर–दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। फिर विकास के सुनहरे सपने उन्हें कैसे दिखाई दे सकता है? इन स्थितियों में कैसे नया भारत–सशक्त भारत आकार ले सकेगा? आइआइटी, एनआइटी और आइआइएसईआर, आइआइएम, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जेएनयू, बीएचयू जैसे विश्वविद्यालयों में भले ही फीस कुछ कम है, लेकिन यहां तक पहुंचने की प्रक्रिया बहुत जटिल एवं प्रतिस्पर्धापूर्ण है। बच्चे संघर्ष करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं और पढ़ाई आसानी से कर लेते हैं। किंतु अब वहां की भी फीस बढ़ाने की कवायद तेजी से होने लगी है। तमाम सरकारी प्रयासों एवं योजनाओं के शिक्षा महंगी होती जा रही है, तो देश का निम्न एवं मजदूर वर्ग यह सोचने को मजबूर है कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे करे। निजी कॉलेजों में तो इतना अधिक पैसा लगता है कि मध्य वर्ग के भी कान खड़े हो जाते हैं, तो फिर निम्न वर्ग की बात ही क्या? यहां बात सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं रह जाती। शिक्षा के साथ एक और विषय है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। वह है, चिकित्सा। जिस तरह गुणवत्ता के मामले में भारत के विश्वविद्यालय पिछड़े हुए हैं, उसी तरह की छवि भारत के अस्पतालों की है। मतलब साफ है कि अच्छी पढ़ाई हो या बेहतर इलाज, जेब में पैसा हो तो पकड़ो विदेश की राह। गंभीर सवाल यह है कि जिसकी जेब में पैसा नहीं है, वह क्या करे? क्या उसे अच्छी पढ़ाई या बेहतर इलाज कराने का हक नहीं है? नए साल में हमें, हमारी सरकारों और इन क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों को इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ़ने चाहिए। हमने जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं तो फिर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र भला अछूते क्यों रहें? जब हम देश के लोगों को ही समुचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो विदेशों के लिये दरवाजें खोलना एवं उन पर सरकार की बड़ी शक्ति का खर्च होना कैसे औचित्यपूर्ण हो सकता है? एक ऐसे देश में जहां वंचित समूह पहले से ही अपनी भावी पीढ़ी को शिक्षित बनाने के लिए कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजर रहा हो, निजी स्कूलों व अस्पतालों की संवेदनहीनता एवं अर्थ लोलुपता से सामाजिक असंतोष एवं विद्रोह के स्वर उभरते रहे हैं। शिक्षा एवं चिकित्सा की भांति पर्यावरण के प्रति उपेक्षा भी अनेक समस्याओं का कारण है। भारत में ग्लोबल तापमान के चलते होने वाला विस्थापन अनुमान से कहीं अधिक है। मौसम का मिजाज बदलने के साथ देश के अलग–अलग हिस्सों में प्राथमिक आपदाओं की तीव्रता आई हुई है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ हो या सिलक्यारा में सुरंग हादसा–भारत में पर्यावरण समस्या को नजरअंदाज करने के परिणाम है। भारत में जलवायु परिवर्तन पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फार एनवायरमेंट एंड डवलपमेंट की जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है ।

एस.एम. शर्मा ने मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर रेलवे, लखनऊ का पद भार किया ग्रहण

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। एस.एम. शर्मा ने उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल के नव–नियुक्त मंडल रेल प्रबंधक के रूप में, निवर्तमान मंडल रेल प्रबंधक, डॉ. मनीष थपल्याल से कार्य भार ग्रहण किया द्य इससे पूर्व श्री शर्मा दिनांक 09 मार्च, 2023 से दक्षिणी रेलवे के तिरुवनंतपुरम मंडल में मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) के पद पर कार्य कर रहे थे ए इसके अतिरिक्त पूर्व में आपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) में समूह महाप्रबंधक (मैकेनिकल), मुख्य राजभाषा अधिकारी और हेवी हॉल इंस्टीट्यूट डीएफसीसीआईएल, नोएडा के डीन के अतिरिक्त प्रभार के साथ राष्ट्रीय भारतीय रेलवे अकादमी, वडोदरा में प्रबंधन में वरिष्ठ प्रोफेसर, रेलवे बोर्ड में निदेशक, ट्रैक्शन और उत्तर रेलवे में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है।

डीएफसीसीआईएल के ग्रुप जीएम के रूप में, एस.एम. शर्मा ने आईआईएससी बैंगलोर के साथ एमओयू के तहत हॉट बॉक्स डिटेक्टरों के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्रेरण और मशीन विजन निरीक्षण प्रणाली का प्रावधान प्राप्त किया और शरोलिंग स्टॉक, क्रू और आपदा प्रबंधन से संबंधित परिचालन और नीतिगत मुद्दों का प्रबंधन पेपर प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और पुस्तकों में रेलवे प्रौद्योगिकी पर शोध पत्र प्रकाशित किए हैं।आप भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसएमई) 1991 बैच के अधिकारी हैं एवं आपने ली कुआन यी स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सिंगापुर से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर किया है और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शेवनिंग सीआरआईएसपी स्कॉलर हैं। वह भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड से रणनीतिक प्रबंधन में पीएचडी (पीटी) कर रहे हैं।

पदभार ग्रहण करने के बाद आपने मंडल के समस्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मंडल में रेल से सम्बंधित प्रगतिशील विभिन्न विकास कार्यो एवं परियोजनाओ की जानकारी ली व सुरक्षित,संरक्षित एवं समयबद्ध रेल परिचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

डीआईजी माघ मेला प्रयागराज के निर्देश पर पुलिस प्रशिक्षण शिविर का हुआ आयोजन

सभी पुलिस कर्मी श्रद्धालुओं से आये शालीनता से पेश - राजेश सोनकर

अयोध्या। माघ मेला प्रयागराज मीडिया सेल के मुताबिक डीआईजी माघ मेला प्रभारी प्रयागराज डॉ राजीव नारायण मिश्र के निर्देश पर रिजर्व पुलिस लाइंस माघ मेला के मानसरोवर सभागार में आयोजित पुलिस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न जनपदों से आए अधिकारियोंध कर्मचारियों को अपर पुलिस अधीक्षक माघ मेला राजेश सोनकर के द्वारा माघ मेला क्षेत्र मे ड्यूटी के दौरान श्रद्धालुओं के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में भी अवगत कराते हुए बताया गया। इस मौके पर उन्होंने मौजूद पुलिस कर्मियों से कहा कि आप सभी लोगों को मेले में आने वाले श्रद्धालुओं से शालीनता एवं श्रद्धा के साथ पेश आते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना होगा।ड्यूटी के साथ दैनिक जीवन में भी मानव द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम एवं प्रभाव मनुष्य के जीवन पर अवश्य पड़ता है। अतः सभी पुलिसकर्मी निष्ठा एवं सेवा की भावना से अपने कर्तव्यों का संपादन करें।इसी क्रम में प्रशिक्षण के दौरान पुलिस उपाधीक्षक माघ मेला दिनेश कुमार यादव के द्वारा पुलिस कर्मियों को तनाव प्रबंधन, आचरण एवं व्यवहार और पुलिस बल के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के अंतिम कलांश रेडियो इंस्पेक्टर माघ मेला के द्वारा मेला क्षेत्र में संचार योजनाओं के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

आज देश और प्रदेश अराजकता का माहौल है : जिलाध्यक्ष

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर।समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश मौर्या के अध्यक्षता में मासिक बैठक में नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी राजेन्द्र सरोज, संजीव साहू,राजेश यादव, संदीप यदुवंशी, जगरनाथ यादव,देवेन्द्र साहू,राकेश पटेल का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया वहीं बैठक को संम्बोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राकेश मौर्या ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे बडा चुनौती यह चुनाव देश के भविष्य को तय करेगा जीस तरह भाजपा सरकार संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहा है आज देश और प्रदेश अराजकता का माहौल है आये दिन हत्या बल्तकार जैसी घटना आम हो गई है लेकिन भाजपा सरकार अपराधियों को सहयोग करने में लगी है अगर आप सभी अपने परिवार एवं बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो भाजपा सरकार को देश और प्रदेश से हटाना ही होगा यह तभी संम्भव जब समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने गावों क्षेत्रों में घर घर जाकर सबसे पहले समाजवादी विचारधारा के वोटरों को बढ़ाने एवं गलत वोटों को कटाने का काम करें और अपने वोटरलिस्ट का निगरानी भी करते रहिए क्योंकि विगत चुनाव में देखा गया है कि आखिर समय में भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी के विचारधारा वाले वोटरों का नाम कटवाने का काम करते है भाजपा सरकार ऐसी ही साजिशों को सफल करने के लिए हर तरीका लगायेंगे इसे लिए सभी समाजवादी पार्टी के साथी सतर्क रहेंऔर भाजपा सरकार की साजिश एवं जन विरोधी कामों को बता कर जनजन को जगाने का काम करें। पूर्व एमएलसी लल्लन प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा सरकार केवल लोगों को गुमराह करती है उनके झूठे वादों को जनता में बताना होगा समझना होगा तभी आने वाले चुनाव में आप ऐसी झूठी सरकार को हटा सकतें है। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व विधायक श्रीराम यादव, लालबहादुर यादव,अरशद खान,डां जितेन्द्र यादव,हिरालाल विश्कर्मा, महेन्द्र यादव,राजेश यादव,हिसामुद्दीन शाह,राहुल त्रिपाठी,रुक्सार अहमद, संजय सरोज, दीपचन्द राम,राजेन्द्र टाईगर, केशजीत यादव,अंखड प्रताप यादव, श्रवण जयसवाल, दिनेश फौजी,लाल मोहम्मद रायनी,दिनानाथ सिंह,मनोज मौर्या, धनश्याम यादव, रामू मौर्या,राम इकबाल,रामजतन,श्याम नरायन बिन्द,अभयराज, महेन्द्र पाल,जेपी यादव, भानुप्रताप मौर्या, शिवजीत यादव,मेवालाल गौतम, हवलदार ,चौधरीआदि संचालन राजेन्द्र यादव ने किया।

अयोध्या में श्री राम मंदिर 22 जनवरी 2024 को अब साकार होगी राम राज्य की परिकल्पना

अयोध्या।(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन धर्म नगरी अयोध्या में देश में सबको 22 जनवरी 2024 का इंतजार है। जैसे–जैसे 22 तारीख नजदीक आ रही है, वैसे–वैसे देशवासियों की अधीरता बढ़ती जा रही है। वक्त काटे नहीं कट रहा है। हर सनातनी और राष्ट्रवादी देशवासी उस घड़ी का साक्षी बनने को आतुर है, जब अयोध्या के श्रीराम मंदिर में श्रीराम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सनातन संस्कृति के आस्थावान इस अवसर को दिव्य, अद्भुत, अलौकिक तथा देश के सम्मान की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाला मान रहे हैं। आशा की जा रही है कि श्रीराम लला के अयोध्या में विराजमान होने के बाद भारत फिर से राम राज्य बनने की ओर अग्रसर होगा।22 तारीख के इंतजार में देश में कुछ वैसा ही माहौल है, जिस प्रकार दीपावली पर्व और स्वाधीनता दिवस से पहले हुआ करता है। देश का हर नागरिक इस दिन दीप प्रज्ज्वलित करने के लिए तत्पर है। सनातन धर्म और संस्कृति में जिनकी आस्था है, उनके लिए जितना 15 अगस्त के दिन का महत्व है, उतना ही जनवरी की 22 तारीख का भी होगा। यह कोई साधारण दिन नहीं है और न ही आसानी से देखना नसीब हो रहा है। यह कई पीढियों द्वारा सदियों तक किए गए प्रयासों–संघर्षों का परिणाम है। श्रीराम के प्रयोजन के लिए जिन लोगों ने अपना सर्वस्व होम कर दिया, यह उन हुतात्माओं के बलिदान का प्रतिफल है।

अयोध्या में बना यह मंदिर देश के लिए सिर्फ पूजास्थल नहीं है बल्कि यह हमारे लिए तप, त्याग और संकल्प प्रतीक और स्थायी प्रेरणापुंज बनने जा रहा है। इसकी वजह साफ है–श्रीराम का यह भव्य मंदिर जिस आंदोलन की बदौलत आकार ले पाया है, वह अर्पण, तर्पण और संकल्प से ओत–प्रोत आंदोलन था। उसी अर्पण, तर्पण और संकल्प की बदौलत ये मंदिर कोटि–कोटि लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति और हमारे राष्ट्र का प्रतीक बनने जा रहा है। जन मान्यता है कि इसी मंदिर में श्री रामलला के विराजित होने के उपरांत राम राज का शिलान्यास भी हो जाएगा। उस राम राज की आधारशिला रखी जाएगी, जिसकी परिकल्पना न जाने कब से हम भारत के लोग कर रहे हैं। सदियों की प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। राम राज की परिकल्पना के साकार होने का वक्त नजदीक आ रहा है।अभी हम जिस कालखंड में जी रहे हैं, वह भारत के लिए क्रांतिकारी, गौरवशाली और बड़े सकारात्मक बदलावों का कालखंड है। पूरी दुनिया हमारी संस्कृति को मान रही है। भारत की गौरवशाली और प्राचीन संस्कृति की तरफ लोगों का रूझान है। पाश्चात्य संस्कृति की ओर खिंचे रहने वाले युवा भी हमारी संस्कृति को पुनरू अंगीकार कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद समेत सौ से ज्यादा संस्थाएं समाज को जाग्रत कर रही हैं। निश्चय ही आने वाला समय अच्छा समय है, इसमें श्रीराम मंदिर मील का पत्थर बनने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो अगले पच्चीस सालों में मंदिर से राम राज की यात्रा का शुभारंभ करने की तैयारी शुरू की है। इसके लिए संघ की एक महत्ती योजना है, जिसके तहत संघ अगले पच्चीस सालों में ऐसे सशक्त भारत का निर्माण करना चाहता है जिसकी बदौलत भारत एक बार पुनरू विश्व गुरु बने। वर्ष 2047 में देश की आजादी के एक सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरएसएस की जो परिकल्पना है, उसे साकार करने के लिए केन्द्र बिंदू राम का मंदिर है और संघ समाज की सभी संस्थाओं को राम राज्य की परिकल्पना के अनुरूप संवैधानिक दायरे में स्थापित करने का रोड मैप बना रहा है। संघ चाहता है कि आगामी पच्चीस सालों में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय ऐसा हो, जिसमें श्रीराम स्वयं बसें और प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन की रचना इसी के अनुरूप करे।आज यह सब करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अतीत में समय चक्र कुछ ऐसे चला, जिससे आसुरी शक्तियां हावी हो गईं। विदेशी आक्रांताओं की वजह से एक लंबे कालखंड तक देश में प्रतिकूल हालात बने रहे। आक्रांताओं ने हमारे विशाल भवन नष्ट कर दिए। हमारे अस्तित्व के खात्मे की कोशिशें की गईं मगर वह श्रीराम को भला किस प्रकार मिटा पाते। उस राम को कैसे मिटाते, जो कण–कण में हैं, हर जन के हृदय में हैं। वक्ती तौर पर भवनों को ढहा देने वाले आक्रांता खुश हो कर चले गए लेकिन जिस प्रकार काले बादलों का अंधेरा छंटने पर सूर्य की सप्त रश्मियां वातावरण को फिर से जगमग कर देती हैं, उसी प्रकार राम मंदिर की बदौलत देश में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव की जगमगाहट होना तय हो गया है। महज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोध के लिए कुछ राजनीतिक दल श्रीराम मंदिर पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ऐसे जनाधार विहीन दलों के मुट्ठी भर नेताओं को समझना चाहिए कि राम का मंदिर किसी एक व्यक्ति अथवा पार्टी का नहीं है। यह ऐसी राष्ट्रीय धरोहर है, जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। करोड़ों लोगों के सहयोग से ही राम जी यह काज संपन्न हो पाया है। करोड़ों लोगों ने इसमें सहयोग किया क्योंकि उनकी मान्यता है कि राम तो घट–घट में हैं। राम किसी एक के नहीं, सबके हैं। समूचे संसार के हैं। भारतवर्ष में करोड़ों लोगों की आस्था के केन्द्र राम हैं तो चीन, इरान, थाईलैंड, मलेशिया व कम्बोडिया में भी श्रीराम कथा एवं प्रसंगों का विवरण मिलता है। नेपालवासियों के माता जानकी से आत्मीय रिश्ते के बारे में भला कौन नहीं जानता। हर किसी को पता है कि श्रीलंका में जन मानस जानकी हरण कथा सुनकर श्रद्धावनत होता है। इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, में रामायण के कई रूप हैं।आज यह धारणा बलवती हो रही है कि राम मंदिर अनंत काल तक समूची मानवता को प्रेरणा देगा तो यह अकारण नहीं है। शास्त्रों में उल्लेख इस बात का है कि श्रीराम के समान कोई नीतिवान समूची धरा पर कभी नहीं हुआ। आज अगर राम राज की परिकल्पना साकार होने की प्रार्थना और उम्मीद की जा रही है तो इसका भी कारण है क्योंकि कोई गरीब व दुरूखी न हो, यह राम राज का उद्देश्य था। श्रीराम का संदेश यह था कि नर–नारी को समान भाव से सुख मिले और बुजुर्गों व बच्चों की सदैव रक्षा हो।कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है कि आखिर राम राज क्या है? दरअसल, राम राज एक सामाजिक व्यवस्था का नाम है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी ने भी की थी। राम राज रूपी सामाजिक व्यवस्था समर्पण एवं त्याग की भावनाओं से ओत–प्रोत है। राम राज ऐसी व्यवस्था का द्योतक है, जिसमें शांति, सत्य और जन भावना का समावेश लाजिमी है। इसमें 'प्राण जाए पर वचन न जाए' की भावना निहित है। लोक भावनाओं के सम्मान के बिना तो राम राज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तुलसी दास जी ने राम राज के बारे में रामायण में जो लिखा है, उसे देखिए। तुलसी दास की कहते हैं– ''दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, रामराज काहु नहीं व्यापा।'' अर्थात राम जी के राज में न देह से संबंधित रोग थे, न दैवीय प्रकोप और न ही भौतिक आपदाओं का प्रभाव व्याप्त था।महात्मा गांधी के 20 मार्च, 1930 को हिन्दी पत्रिका 'नवजीवन' में 'स्वराज्य और रामराज्य' शीर्षक से प्रकाशित लेख में राम राज्य का बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया गया है। गांधी जी लिखते हैं कि ''स्वराज्य के कितने ही अर्थ क्यों न किए जाएं, तो भी मेरे नजदीक तो उसका त्रिकाल सत्य एक ही अर्थ है, और वह है रामराज्य, यदि किसी को रामराज्य शब्द बुरा लगे तो मैं उसे धर्मराज्य कहूंगा। रामराज्य शब्द का भावार्थ यह है कि उसमें गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी। सब कार्य धर्म पूर्वक किए जाएंगे और लोकमत का हमेशा आदर किया जाएगा। ज्सच्चा चिंतन तो वही है, जिसमें रामराज्य के लिए योग्य साधन का ही उपयोग किया गया हो. यह याद रहे कि रामराज्य स्थापित करने के लिए हमें पाण्डित्य की कोई आवश्यकता नहीं है. जिस गुण की आवश्यकता है, वह तो सभी वर्गों के लोगों– स्त्री, पुरुष, बालक और बूढ़ों– तथा सभी धर्मों के लोगों में आज भी मौजूद है. दुरूख मात्र इतना ही है कि सब कोई अभी उस हस्ती को पहचानते ही नहीं हैं. सत्य, अहिंसा, मर्यादा–पालन, वीरता, क्षमा, धैर्य आदि गुणों का हममें से हरेक व्यक्ति यदि वह चाहे तो क्या आज ही परिचय नहीं दे सकता?श्रीराम का मार्ग मानवता का मार्ग है। जब–जब हम श्रीराम के मार्ग पर चले हैं तो सुख का विस्तार हुआ है, समृद्धि ने पांव पसारे हैं और विकास ने बाहें फैलाई हैं लेकिन यह भी सत्य है कि जब–जब हम राम जी के रास्ते से भटके हैं तो हमारा पतन हुआ है। अब हम सही रास्ते पर हैं यानी राम के मार्ग पर हैं। हमारा मूल रास्ता ही यही है क्योंकि राम हमारी संस्कृति के आधार हैं। वह हमारे राष्ट्र की मर्यादा और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं।

रेल का चक्का होगा जाम : शिवगोपाल मिश्रा

पुरानी पेंशन बहाली के लिए 8 जनवरी से चार दिवसीय भूख हड़ताल

मृत्युंजय प्रताप सिंह संवाददाता

लखनऊ। पुरानी पेंशन योजना बहाली मंच के तत्वाधान में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आन्दोलन तेज हो गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आहवान पर 6 जनवरी को आयोजित केन्द्र और राज्य कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों के लिए आयोजित खिचड़ी भोज के उपरान्त पत्रकारों से बातचीत कर रहे रेलवे मैन्स यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल न कर हठधर्मिता का परिचय दे रही है। पूरा देश का कर्मचारी एनपीएस की व्यवस्था से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आक्रोषित केन्द्र और राज्य के कार्मिकों ने एक जनमत संग्रह कराकर इस बॉत का स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह शत प्रतिशत हड़ताल के पक्ष में है। यदि अब भी समय रहते सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी नही करती तो एक बार फिर 1974 के बाद पुरानी पेंशन बहाली के लिए रेल का चक्का जाम कर दिया जाएगा।

पत्रकारों से बॉतचीत करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहाकि सरकार अपना अडियल रवैया छोड़ दे नही तो हड़ताल को रोकना मुश्किल होगा। प्रदेश के कर्मचारी,शिक्षक लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए धरना, ज्ञापन, मशाल जुलुस कर सरकार का ध्यान आकृषित करा रहे है।संयुक्त मंच द्वारा राजधानी में 27 जून 23 को तथा 10 अगस्त 23 को रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में पहुंचकर रैली कर चुके है। सरकार कर्मचारी शिक्षकों के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे। इस परिपेक्ष्य में फिलहाल पूर्व घोषित कार्यक्रम 8 जनवरी से 11 जनवरी तक चेतावनी स्वरूप भूखहड़ताल की जा रही है। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली मंच की बैठक में पत्रकार वार्ता से पूर्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, रेलवे मैन्स यूनियन, पोस्टल, आयकर, प्राथमिक शिक्षक संघ, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ, सहित अनेक कार्मिक और शिक्षक संघों के चार दिवसीय भूखहड़ताल को भीषण ठण्ड को देखते हुए 24 घन्टे की जगह प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक किये जाने का निर्णय लिया।पत्रकार वार्ता में परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव, परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष इं. एन.डी.द्विवेदी, अपर महामंत्री डा. नरेश कुमार, ज्वाइंट पेंशनर्स वेलफेयर काउन्सिल के संयोजक एन.पी. त्रिपाठी, डिप्लोमा इंजीनियर्स पेंशनर्स से इं. शिवशंकर दुबे, सुशील पाण्डेय अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ, सचिवालय पेंशनर्स एसोसिएशन के ओंकारनाथ तिवारी और डिप्लोमा इंजीनियर्स दिवाकर राय, संतोष तिवारी मौजूद रहे। खिचड़ी भोज के दौरान सिर्फ हड़ताल पर चर्चा कर्मचारी समस्याओं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ (लोक निर्माण विभाग) उ.प्र0 के संयुक्त तत्वाधान में डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ भवन (लोक निर्माण विभाग) राजभवन के समाने लखनऊ में खिचड़ी भोज का आयोजन हुआ। रेलवे मेन्स यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा मुख्य अतिथि रहे। खिचड़ी भोज में कर्मचारी समस्याओं, पेंशन आन्दोलन व सरकार के रवैये पर चिन्तन किया गया। सभी पदाधिकारियों द्वारा कर्मचारी समस्याओंध्माँगों पर केन्द्र व राज्य सरकार के रुख पर चिन्ता व आक्रोश व्यक्त किया गया। खिचड़ी भोज में सभी केन्द्रीय कर्मचारी संगठनों राज्य कर्मचारी संगठनों व शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। खिचडी भोज के मेजबान इं0 हरि किशोर तिवारी व इं0 एन0डी0 द्विवेदी रहे। खिचड़ी भोजन में प्रमुख रुप से डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अध्यक्ष इं0 एच0एन0 मिश्रा, रेलवे मैन्स यूनियन आर0के0 पाण्डे, आयकर से रविन्द्र कुमार सिहं, केन्द्रीय कर्मचारी फेडरेशन से कामरेड एस0बी0 यादव, श्री एस0यू0 शाह (।पथ्) प्रदीप वर्मा, आकाशवाणी, संजय वर्मा, पासपोर्ट, एस0बी0 सिंह, दूरदर्शन, पी0एस0 गर्ग, (एन0ई0 रेलवे) सतीश पाण्डेय जवाहर भवन, इं. एस.पी. मिश्रा, रामसुरेश, कामरेड विभूति मिश्रा, इं0 प्रकाश चन्द, इं0 श्रवण कुमार यादव, अमिता त्रिपाठी, सुभाष चन्द्र तिवारी, धर्मेन्द्र सिंह, अमरजीत मिश्रा, अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव, रेनू शुक्ला, सुशील पाण्डेय, अशोक दुबे, इं0 जी0एन0 सिंह, श्री रवि भाटिया, अनुज कुमार शुक्ला,संदीप सिंह चौहान, इं. एस. डी. द्विवेदी, श्री नरेश कौशिक, योगेश त्यागी, सुनील दत्त श्रीवास्तव, इं0 डी0बी0 सिंह, वीरेन्द्र यादव, सुनील यादव, शिवकुमार यादव, सुभाष मिश्रा, सहित तमाम संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे।

प्राण प्रतिष्ठा में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी नहीं कर सकेंगे स्मार्ट फोन का इस्तेमाल

डीजी कानून व्यवस्था द्वारा जारी पत्र के मुताबिक सुरक्षा के चलते लिये गये यह निर्णय

अयोध्या।(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता) 22 जनवरी को श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के आयोजनों के दौरान कहीं कोई चूक न हो इसके लिए हर स्तर पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है।इन अवसरों पर संवेदनशीलता को देखते हुए पहली बार पुलिसकर्मियों के ड्यूटी के दौरान स्मार्टफोन के उपयोग पर रोक लगा दी गई है।डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार द्वारा जारी पत्र के मुताबिकइस दौरान पुलिसकर्मियों से कोई लापरवाही न हो,इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान स्मार्टफोन का उपयोग न करने की हिदायत दी गई है।डीजी कानून–व्यवस्था प्रशांत कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अक्सर यह देखा गया है कि फील्ड ड्यूटी के दौरान अधिकतर पुलिसकर्मी स्मार्टफोन का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, जिससे वे एकाग्रचित होकर पूरी सतर्कता से ड्यूटी नहीं करते।उन्होंने सभी सभी पुलिस कमिश्नर, एसएसपी व एसपी को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि कहा गया है कि 22 जनवरी को अयोध्या और 26 जनवरी को पुलिसकर्मियों को संवेदनशील व महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात किया जाएगा।ऐसी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को विधिवत निर्देश दें कि ड्यूटी के दौरान अनावश्यक रूप से स्मार्टफोन का उपयोग कतई न करें। ड्यूटी के दौरान बेहद जरूरी होने पर ही फोन पर वार्ता करें।

हिन्दी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान की एक बैठक दस जनवरी को

अयोध्या।हिन्दी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान की एक बैठक दस जनवरी को प्रातः 11 बजे से विश्व विराट विजय राघव मंदिर नया घाट अयोध्या (निकट पंजाब नेशनल बैंक)में आहूत की गई है।विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित उक्त बैठक में ष्अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हिंदीष विषय पर परिचर्चा के साथ साथ कवियों का भी समागम होगा।बैठक में संस्थान की सदस्यता अभियान में सक्रियता लाने, मातृभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने व विश्व की सम्पर्क भाषा बनाए जाने,मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरीअयोध्या में भव्य अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भवन व वाचनालय की स्थापना आदि विषयों पर विस्तृत पर चर्चा की जाएगी। समस्त साहित्य प्रेमियों से उक्त अवसर पर समय से उपस्थित होने के अपील की गई है।

पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य पंकज कुमार श्रीवास्तव ने रेल मंत्री से किया आग्रह

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य पंकज कुमार श्रीवास्तव ने रेल मंत्री से 20 जनवरी से 30 जनवरी तक पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न प्रमुख रेलवे स्टेशनों से अयोध्या धाम तीर्थ स्थल तक विशेष रेल गाड़ियों का संचालन श्रद्धालुओं हेतु आग्रह किया है। जेड. आर.यू.सी.सी. सदस्य पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि श्री राम प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में सम्मिलित होने के लिए संपूर्ण प्रदेशवासी काफी उत्सुक है और वह अयोध्या धाम पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे महान पर्व पर सवारीध मेल ध् एक्सप्रेस रेल गाड़ी का चलाया जाना नितांत आवश्यक है। भाजपा नेता पंकज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार अयोध्या धाम तक ट्रेन संचालन होने से आम नागरिकों एवं दर्शनार्थियों को सुविधा मिलेगी।

चल रही यू पी जोड़ो यात्रा के समापन पर अयोध्या से ज्यादा ज्यादा संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कूच करेंगे-वेद सिंह कमल

अयोध्या।उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय के नेतृत्व में चल रही यू पी जोड़ो यात्रा के समापन पर अयोध्या से ज्यादा ज्यादा संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कूच करेंगे।उक्त बातें महानगर कांग्रेस अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने कांग्रेस कार्यालय पर महानगर कमेटी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही।महानगर अध्यक्ष वेद कमल ने कहा कि ष्यू०पी० जोड़ो यात्राष दिनांक 4 जनवरी को सहारनपुर से प्रारंभ हुई यह यात्रा 6 जनवरी को लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ जनपद में यह यात्रा जन जनसम्पर्क करते हुए शहीद स्मारक, लखनऊ पर पहुँचेगी,। जहाँ पर शहीदों को नमन् करने के उपरान्त आगामी राजनैतिक संकल्प लिया जायेगा।पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा ने कहा लखनऊ में यात्रा के समापन पर अयोध्या से बड़ी संख्या में कांग्रेसी सम्मिलित होंगे।बैठक में प्रमुख रूप से जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम, महानगर उपाध्यक्ष फ्लावर नकवी, महानगर महासचिव रामेंद्र त्रिपाठी ,जनार्दन मिश्रा,प्रवीण श्रीवास्तव, सुरेंद्र सिंह सैनिक आदि उपस्थित रहे ।

प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अग्निशमन विभाग नहीं छोड़ रही कोर कसर

पर्याप्त संख्या में दमकल व फायर कर्मी रहेंगे तैनात - सीएफओ

अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पुलिस प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।यहां तक कि पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने पत्र के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में तैनात पुलिस कर्मियों के स्मार्ट फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है।वही अग्निशमन विभाग भी इस कार्यक्रम को सकुशल सम्पन्न कराने के लिये कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।इसके लिए अग्निशमन विभाग द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रमुख स्थलों पर पर्याप्त संख्या में फायर ब्रिगेड के कर्मी को फायर एस्टिंग्यूशर, फायर पंप यूनिट, बड़े दमकल,हाई प्रेशर पंप, क्रैश फायर,फोम दमकल के साथ तैनात रहेंगे।यह जानकारी सीएफओ एमपी सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी कार्यक्रम स्थलों को चिह्नित कर इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है कि उस दिन अतिथियों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वह अग्निशमन मानक के अनुसार हो रहा है।उन्होंने बताया कि टेंट सिटी तीर्थ क्षेत्र पुरम,बाग बिजेसी, बड़ी छावनी, कथावाचकध्अमृत महोत्सव स्थल बड़ी छावनी, सर्किट हाउस, रामकथा पार्क, साकेत पेट्रोल टंकी, कोतवाली अयोध्या, साकेत महाविद्यालय व कारसेवक पुरम मे 2500 लीटर क्षमता वाले दमकल के साथ फायर कर्मी मौजूद रहेंगे।इसी तरह हवाई पट्टी पर दो क्रेश फायर, हेलीपैड, राम कथा पार्क कार्यक्रम क्षेत्र तथा नया घाट, पुलिस लाइन 4500 लीटर की क्षमता दमकल व वहां पर फायरकर्मी तैनात रहेंगे।इसी तरह पीएम लैंडिंग ग्राउंड पर दो फोम टेंडर तैनात रहेंगे।इसी तरह से सरयू पुल के नीचे बाई तरफ,राम जन्मभूमि, आरती स्थल,राम कथा पार्क में जलापूर्ति स्थल, टेढ़ी बाजार, मणिराम छावनी, हनुमान गढ़ी, नागेश्वर मंदिर,कनक भवन,टेंट सिटी, टेंट सिटी विद्यापीठ,टेंट सिटी ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा,1008 हवनकुंड स्थल पर छोटे बड़े फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फायरकर्मियों के साथ तैनात रहेगी।

अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी 2024 से, 05 वर्ष हेतु, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि ''भारत सरकार द्वारा, योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी 2024 से, 05 वर्ष हेतु, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।''

उक्त के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत माह–जनवरी, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का, निःशुल्क वितरण 10 जनवरी 2024 से 25 जनवरी 2024 के मध्य किया जायेगा।

उक्त वितरण अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूं तथा 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा० चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 25 जनवरी 2024 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।

तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व में जारी सोशल डिस्टेन्सिंग के निर्देशो का पालन कराते हुए नियमानुसार लाभार्थियोंध राशनकार्डध ारकों में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाये।

लेखपालों तथा कानूनगों की संयुक्तटीम बनाकर जमीन विवाद के मामलों की जांच कराई जाए : जिलाधिकारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ।

संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 45 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें से 05 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर एक सप्ताह के अंदर निस्तारित करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में जो भी शिकायतें प्राप्त हुई है उनकी जांच करके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए। सम्पूर्ण समाधान दिवस पर ज्यादातर शिकायतें जमीन विवाद के संबंध में प्राप्त हुई, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि राजस्व तथा पुलिस विभाग की टीम मौके पर जाकर निरीक्षण करें तथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शिकायतों का निस्तारण करायें।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में विशेष ध्यान दें, निस्तारण में लापरवाही पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि लेखपालों तथा कानूनगों की संयुक्त टीम बनाकर जमीन विवाद के मामलों की जांच कराई जाए तथा उसका नियमानुसार समाधान कराया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जमीन विवादों के प्रकरण में यदि कोई भी लेखपाल लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जमीन विवादों का त्वरित निस्तारण शासन की प्राथमिकता है इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डा. अजय पाल शर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 लक्ष्मी सिंह, उप जिलाधिकारी सदर रिषभ पुडंरिक, अतिरिक्त उपजिलाधिकारी प्रजाक्ता त्रिपाठी सहित अन्य जनपद एवं तहसील स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन : नए यौगिक साथियों के साथ हुए मौजूद, छात्रों को मिलेगा उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण का सुनहरा अवसर

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। बक्शी का तालाब स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पिछले दिनों में 3 कंपनियों के साथ एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) के साइन हुआ है। कोडिंग ब्लॉक्स लखनऊ नामक कंपनी के निदेशक अभिज्ञान विक्रम सिंह ने बताया है कि वे विभिन्न टूल्स को कवर करेंगे जैसे कि नोड– जेएस, बूटस्ट्रैप, सीएसएस, बेबेल, और कई अन्य तकनीक पर प्रशिक्षण पर अनुबंध किया गया । टीपीएमसी इन्फो सोल्यूशन्स प्रा. लव पंत जो कि प्रबंधक (विक्रय और विपणि) पद पर हैं, उन्होंने बताया कि उनका प्रशिक्षण का एजेंडा च्6 प्राइम वेरा पर प्रशिक्षण दिया जाना तय हुआ है। तीसरी कंपनी लॉजिक प्रो इन्फोसिस्टम की ओर से निदेशक कृष्णा एम. पांडेय ने बताया कि वे छात्रों को फुल स्टैक डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, एम्बेडेड सिस्टम और आईओटी, डेवऑप्स और ब्लॉकचेन, ऑटोकैड और सॉलिडवर्क्स पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जो मैकेनिकल अभियंत्रण के लिया सहायक होगी औद्योगिक जगत में इन्ही तकनीक का प्रशिक्षण हो रहा है। एसआर कॉलेज के निदेशक डॉ. डी.पी. सिंह ने सभी एमओयू को हस्ताक्षर करके सभी को बधाई दी और बच्चों को सभी उन्नत तकनीकों के बारे में पता चलने के लिए खुशी जताई।

एस आर ग्रुप के चेयरमैन पवन सिंह चौहान (एमएलसी) छात्रों में दक्षता बढ़ाने पर ध्यान देने पर जोर देने को कहा जिससे इंडस्ट्री में जाकर आपको दुसरो से अधिक महत्व मिलेगा। सभी अथितियो को समृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

श्री राम महायज्ञ की कर्मकांड दिग्दर्शिका (पोथी) का विमोचन समारोह सम्पन्न

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। श्री राम महायज्ञ की कर्मकांड दिग्दर्शिका (पोथी) का विमोचन हनुमान सेतु मंदिर में पूजन पूर्वक संपन्न हुआ। बाबा नीब करौरी महाराज जी की कृपा और अंतः प्रेरणा से पोथी के संपादक अतुल कपूर ने पहले पोथी को श्री हनुमान जी के चरणों में रखा। तत्पश्चात बाबा नीब करौरी महाराज जी की प्रतिमा के सम्मुख, उनके चरणों में रखा।

तत्पश्चात हनुमान सेतु मंदिर ट्रस्ट के सचिव दिवाकर त्रिपाठी जी (सेवानिवृत्ति वरिष्ठ आईएएस) के साथ हनुमत कृपा मासिक पत्रिका के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार नरेश दीक्षित, सह–संपादक रमेश शर्मा तथा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के लखनऊ जनपद के महामंत्री आचार्य आर एल पाण्डेय ने संयुक्त रूप से श्री राम महायज्ञ कर्मकांड दिग्दर्शिका का विमोचन किया। इस कर्मकांड दिग्दर्शिका के सह संपादक मनु शर्मा है।

उल्लेखनीय है कि इस श्श्री राम महायज्ञ कर्मकांड दिग्दर्शिकाश में वैदिक और लौकिक मंत्रों को शास्त्र सम्मत व क्रमबद्ध तरीके से संपादित करके, बड़े यज्ञों के लिए कर्मकांड निर्मित किया गया है। पिहानी में आगामी 14 जनवरी को बाबा मैरिज हॉल में आयोजित 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ में इस पोथी के द्वारा यज्ञीय कर्मकांड, गायत्री प्रज्ञा पीठ, पिहानी की टोली द्वारा संपन्न कराये जाएंगे। सर्वतोभद्र मंडल के पूजन के मंत्रों का हिन्दी पद्यानुवाद भी अतुल कपूर ने किया है।

भारती फाउंडेशन के चेंजमेकर अवॉर्ड्स ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में उत्कृष्टता का जश्न मनाया

पुरस्कार समारोह के दौरान 27 विजेताओं की घोषणा की गई।

मृत्युंजय प्रताप सिंह

लखनऊ। भारती फाउंडेशन द्वारा आयोजित चेंजमेकर अवॉर्ड्स में ऐसी कॉरपोरेट कंपनियां और व्यक्ति एकसाथ दिखाई दिए जिन्होंने वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर दुनिया की रचना करने की पहल की हैं औरध्या ऐसी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इस अवसर पर भारती फाउंडेशन के सह–अध्यक्ष (भारती एंटरप्राइजेज के उपाध्यक्ष) श्री राकेश भारती मित्तल, भारती फाउंडेशन की ब्म् सुश्री ममता सैकिया, भारती फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य – लेफ्टिनेंट कर्नल विजय चड्ढा, भारती एंटरप्राइजेज के उपाध्यक्ष – श्री अखिल गुप्ता, भारती ग्रुप की कंपनियों और पार्टनर कंपनियों के लीडर्स के साथ–साथ फाउंडेशन के समर्थक और वॉलंटियर्स उपस्थित थे।

इस वर्ष पुरस्कारों की 6 श्रेणियों के तहत 85 नामांकन प्राप्त हुए थे जिनमें जिनमें भारती समूह की कंपनियों के लिए एम्घ्प्ध्लॉइई एन्घ्गेजमेंटय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक पहलेंय तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत लोकोपकार शामिल हैं। इन नामांकनों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर आजीविका, खेल आदि के क्षेत्र में कार्यनीतिक, अभिनव और दीर्घकालिक पद्धतियों द्वारा समाज पर डालले गए आशावादी प्रभाव का दावा किया गया था। इस वर्ष के विजेताओं में शामिल हैंरू

इंडिविजुअल फिलानथ्रॉपी नैशनल

स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पोपट चंदू रसल ने अकेले 2022–23 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 20,000 से अधिक स्वदेशी पेड़ लगाए।

भ्ब् इंक के सत्यनारायण के. कर्नाटक राज्य्य के बेंगलुरू शहर में बच्चों की भूख कम करने और सरकारी स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध्ध कराने के लिए स्वयंसेवा कर रहे हैं।

भ्ब् इंक की एक अन्य विजेता, अरुंधति भट्टाचार्य ने प्।भ्ट (इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज) के लिए स्वेच्छा से काम किया, और मानसिक कल्याण और परामर्श सत्रों के माध्यम से 200 महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव डाला।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के सुदर्शन बेंगानी को सामुदायिक सेवाओं जैसे रक्तदान, पक्षी अस्पतालों की सहायता, भोजन दान और झुग्घी–झोपड़िघ्यों के बच्चों की सहायता करने में उनके नियमित योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

भारती एयरटेल लिमिटेड की पूर्णिमा कपूर ने सीमित पहुंच रखने वाले गरीब छात्रों को उत्घ्कृष्ट शिक्षा, कैरियर के अवसरों और मार्गदर्शन की सहायता करने के लिए स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता।

सोशल इनिशिएटिव नैशनल

सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने अपने प्रोजेक्ट मेडिकल च्वै के लिए उन क्षेत्रों के लिए संकल्पना की है जहां स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की कमी है।

सिग्निफाई इनोवेशन इंडिया लिमिटेड की परियोजना, श्खेल ज्योतिश, बच्चों के लिए सुरक्षित और अच्छी रोशनी वाली जगह उपलब्ध्धा कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहित करती है।

अवाया इंडिया प्रा. लिमिटेड को उनकी पहल श्रोड टू करियरश के लिए के लिए, कौशल निर्माण के अवसर प्रदान करने और वंचित युवाओं और किशोरों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए है।

इंडस टावर्स की श्अभिनव परियोजना, उनके प्रमुख सीएसआर कार्यक्रम श्सक्षमश के तहत श्डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैनश ने भारत के ग्रामीण और शहरी हिस्सों में वंचित समूहों के लिए डिजिटल साक्षरता को पहुंचाया।

ईसीआई टेलीकॉम इंडिया प्रा. लिमिटेड की पहल श्राइट टू एजुकेशन फॉर एव्री चाइल्ड ' एक हतेंतवव्ज छळव् के स्कूल की क्षमता निर्माण का समर्थन करती है, जिससे 2,000 से अधिक वंचित छात्रों को लाभ मिलता है।

एरिक्सन इंडिया प्रा. लिमिटेड ने अपनी पहल, श्एरिक्सन सेंटर ऑफ एक्सीलेंसश के लिए स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता, जो युवाओं को 5जी और उभरती प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण के माध्यम से दूरसंचार उद्योग में कौशल की कमी को दूर करती है, उन्हें गतिशील कॉर्पोरेट दुनिया के लिए जरूरी कौशलों से लैस करती है।

कर्मचारी सहभागिता पुरस्कार (देश के ग्रामीण हिस्सों के वंचित बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए स्वयंसेवा करने और पे–रोल दान करने की दिशा में भारती समूह की कंपनियों के प्रयासों को सम्घ्मानित करना)रू

भारती रियल्टी लिमिटेड ने लगातार 3 वर्षों से अधिक समय से पे–रोल दान के द्वारा 100ः कर्मचारियों को शामिल करके इस नेक कार्य में लगी हुई है।

डेल मोंटे फूड्स प्रा. लिमिटेड लगातार भारती फाउंडेशन के साथ जुड़ा रही है और अपने 80ः से अधिक कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया है।

बीटल टेलीटेक लिमिटेड के 60ः कर्मचारियों ने पेरोल दान करने के कार्यक्रम में भाग लिया।

इंडिविजुअल फिलानथ्रॉपी इंटरनैशनलरू हारिफिडी राकोतोबे (एयरटेल मेडागास्कर एस.ए.), माइकल ओपवोनियो (एयरटेल युगांडा लिमिटेड (और ऐन नजेरी (एयरटेल नेटवर्क्स केन्या लिमिटेड) । इसके अलावा, एयरटेल नाइजीरिया, एयरटेल नेटवर्क्स केन्या लिमिटेड, एयरटेल तंजानिया लिमिटेड,एयरटेल नेटवर्क्स जाम्बिया पीएलसी और भारत में विभिन्न एयरटेल सर्कल के कर्मचारियों को दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के प्रति उनके अनुकरणीय योगदान के लिए पुरस्कार मिला है।

भारती फाउंडेशन की ब्म् सुश्री ममता सैकिया ने चेंजमेकर पुरस्कारों के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, श्भारती फाउंडेशन में हम लोग कायाकल्घ्प करने वाली ऐसी पद्धतियों की शक्ति पर विश्वास करते हैं जो कि दीर्घकालिक हों। चेंजमेकर पुरस्कार अनुकरणीय कार्यों द्वारा समाज पर आशावादी प्रभाव डालने में व्यक्तियों और कॉरपोरेट कंपनियों के सामूहिक प्रयासों का प्रमाण हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्घ्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता विभिन्न उद्योगों में दूसरों के लिए प्रेरणा के रूप में काम करती है।

2008 में चेंजमेकर पुरस्घ्कार शुरू किए गए थे। ये दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों की दिशा में कॉरपोरेट कंपनियों के साथ–साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों के सराहनीय प्रयासों को सम्घ्मानित करते हैं। यह पुरस्कार लोगों को सामुदायिक परिवर्तन, पर्यावरणीय पहल और स्वयंसेवी कार्यक्रमों में उनके ऐसे कामों को दिखाने के लिए एक आम मंच उपलब्ध्ध कराता है, जिनसे समाज में सार्थक बदलाव आया है।

अटल भूजल योजना की रैंकिंग में यूपी सिरमौर, बड़े बड़े राज्यों को छोड़ दिया पीछे

7 राज्यों में चल रही योजना में यूपी ने जिले, ब्लाक और ग्राम पंचायत स्तर पर कायम किये रिकार्ड

योगी सरकार में जल शक्ति विभाग की पहल लाई रंग, बुंदेलखंड के जिलों में बढ़ रहा भूगर्भ जल

योजना की दिसम्बर 2023 की जारी रैंकिंग में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान से आगे निकला यूपी

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों जरूरत भर के पानी के लिए भी लोगों को तरसना पड़ता था. ग्रामीणों ने पानी की किल्लत को अपनी नियति मान लिया था. ऐसा अब बिल्कुल नहीं है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले साढ़े छह साल में उत्तर प्रदेश की इस नियति को बदलकर रख दिया है. गांव गांव तक पानी पहुंचाना हो या उसकी गुणवत्ता यूपी सिरमौर है.अटल भूजल योजना की रैंकिंग में भी यही साबित हुआ है.

हर घर नल से जल योजना के माध्यम से पानी तो गांव–गांव पहुंच ही रहा है साथ ही जल संरक्षण में भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में अव्वल हो चुका है. भू जल स्तर में गिरावट को रोकने में देश के छह राज्यो से यूपी कहीं आगे निकल गया है. प्रदेश को भूजल योजना की रैंकिंग में अव्वल नंबर मिला है.

'इन राज्यों को छोड़ दिया पीछे'

जिला, ब्लाक और ग्राम पंचायत स्तर पर तेजी से चल रहे भूगर्भ जल को बचाने के अभियानों की वजह से यूपी गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. भूजल स्तर को बेहतर करने और किसानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से योजना यूपी में काफी कारगर साबित हुई है. भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन और नियमन को यूपी के 10 जिलों (चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, झांसी, मुज्जफरनगर, शामली, ललितपुर, महोबा, बागपत और मेरठ) में तेजी से पूरा किया जा रहा है।

'यूपी में अटल भूजल योजना कायम कर रही नए आयाम'

ताजा आंकड़े दिसम्बर 2023 में जारी किए गए हैं. इस रैंकिंग में यूपी ने अटल भूजल योजना में राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है. यूपी के बाद महाराष्ट्र, तीसरे पर मध्य प्रदेश है. जबकि हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान इन तीनों राज्यों से पीछे हैं. जिला रैंकिंग में सभी सात राज्यों के 78 जिलों में यूपी के पांच जिले (शामली, झांसी, ललितपुर,मुज्फ्फरनगर, हमीरपुर) टॉप 10 में शामिल हुए हैं. इसी तरह से ब्लाक स्तर पर जारी रैंकिंग में देश के 193 ब्लाकों में यूपी के पांच ब्लाक (झांसी का बबीना, शामली का कंधला, हमीरपुर का मुस्करा, ललितपुर का तालबेहट, झांसी का मऊरानीपुर) टॉप 10 में हैं. इसी तरह से ग्राम पंचायत स्तर पर जारी रैंकिंग में देश के 8353 ग्राम पंचायतों में यूपी की 7 ग्राम पंचायतें शामिल हुईं है. इन ग्राम पंचायतों में मऊरानीपुर झांसी की भडरवारा ग्राम पंचायत, चकारा ग्राम पंचायत, खंडरका ग्राम पंचायत, रोरा ग्राम पंचायत और खरखोडा मेरठ की आढ़ ग्राम पंचायत, बुढाना मुज्जफरनगर की अलीपुर अलटना ग्राम पंचायत और फुगाना ग्राम पंचायतें शामिल हैं.

'भूजल के बाद भूगर्भ जल के स्तर को सुधरेंगे हमारे अफसररू स्वतंत्र देव सिंह'

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी में भूजल संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन और नियमन के 10 जिलों में तेजी से चल रहे कार्यों की सराहना की है.उन्होंने नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव समेत समस्त अधिकारियों और जमीनी स्तर तक योजना को ले जा रहे इंजीनियरों और कर्मचारियों की भी तारीफ की है. उन्होंने कहा है कि योजना से बहुत जल्द यूपी में भूमिगत जल की कमी की समस्या से निजात मिल जाएगी और आने वाले समय में पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहेगी.

गंगा जमुनी तहजीब भाईचारा के प्रतीक अयोध्या धाम अयोध्या की मशहूर दरगाह हजरत शाह इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह आलेह की दरगाह

अयोध्या।अयोध्या मे गंगा जमुनी तहजीब भाईचारा के प्रतीक अयोध्या धाम अयोध्या की मशहूर दरगाह हजरत शाह इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह आलेह के तीन दिवसीय सालाना उर्स 6 ,7 ,8 फरवरी 2024 के संबंध में दरगाह के गद्दी नशीन ध् प्रबंधक अल्हाज बाबा मोहम्मद जुनैद कादरी की सरपरस्ती में एक बैठक दरगाह शरीफ पर बृहस्पतिवार को हुई जिसमें दरगाह से जुड़े जिम्मेदारान व शहर के अन्य लोग मौजूद थे श्री बाबा कादरी ने लोगों से विचार विमर्श कर उर्स को बेहतर तरीके से किए जाने पर बात की और लोगों के सुझाव भी लिए।हाजी मो जुनैद कादरी ने बताया हर साल की तरह इस वर्ष भी दरगाह हजरत शाह इब्राहिम शाह रहमतुल्लाह आलेह का सालाना उर्स दिनांक 6, 7, 8, फरवरी 2024 को बड़ी ही शान शौकत के साथ परंपरागत मनाया जाएगा।

हिन्दी सान्ध्य दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित ।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0–7007415808,9628325542,9415034002

RNI सन्दर्भ संख्या – 24/234/2019/R-1
deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से सम्बन्धित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायलय होगा।